A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 22 मई, 2026
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 259, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

पेड़ हरा क्यूं सूख चला
चिड़ियों की पीड़ा में सुन।
गुड़िया गुड्डा याद दिला
मीता! छेड़ पुरानी धुन।
दु:ख नदी का पूछ जरा
आ जा शंख सीपियां चुन।
कह गई रात कोई आया
तेरी पायल की रुनझुन।
बेद पुरान को आग लगा
आज तो केवल रोटी गुन।
सच्ची सच्ची कहते हैं
हममें एक यही औगुन ।।

– विवेक चतुर्वेदी

प्रसंगवश

क्या नया ट्रांसजेंडर संशोधन कानून ट्रांस पुरुषों के खिलाफ है?

पूर्वी गुप्ता

साल 2021 की बात है। समर शर्मा 18 साल के हो चुके थे जो हरियाणा के करनाल ज़िले के एक गांव के रहने वाले हैं। वे घरवालों को समझाते थक चुके थे कि वे अपने जन्म के समय दी गई लैंगिक पहचान के साथ अब नहीं जी सकते। समर एक ट्रांसजेंडर पुरुष हैं। वे दिल्ली में रहकर एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। पिछले पाँच सालों में उन्होंने सबसे बड़ा सपना पूरा किया। उन्होंने सरकारी पहचान पत्रों पर अपना जेंडर 'पुरुष' दर्ज करवाया। यह उनके लिए क़ानूनी मान्यता, सम्मान और गरिमा के साथ जीने के लिए ज़रूरी था। उनके आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों में भी उन्हें पुरुष के तौर पर मान्यता मिली हुई है। उनके पास सरकार की तरफ़ से दिए जाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कार्ड के साथ-साथ जेंडर संगति सर्जरी (जेंडर अफर्मिंग सर्जरी) के लिए ज़रूरी जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया (जीआईडी) प्रमाण पत्र भी है। जीआईडी प्रमाण पत्र एक चिकित्सकीय दस्तावेज़ होता है। इसमें विशेषज्ञ यह दर्ज करते हैं कि व्यक्ति अपनी वास्तविक जेंडर पहचान और जन्म के समय निर्धारित जेंडर के बीच असंगति की वजह से मानसिक तौर पर असहज महसूस कर रहा है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक पास किया है। इस बिल में सबसे अहम संशोधनों में एक है- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 'सेल्फ आइडेंटिटी' के प्रावधान का हट जाना। अब समर को लग रहा है कि कहीं उनकी जेंडर पहचान ही संकट में न आ जाए। यह बिल कानून बनकर लागू हो चुका है।

वरिष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी बिल की बारीकियों को समझाते हुए कहती हैं कि इस विधेयक ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा को केवल सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोगों तक सीमित कर दिया है। जैसे, किन्नर, हिजड़ा, अरावनी, जोगता और इंटरसेक्स विविधताओं वाले व्यक्ति ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति माने जाएंगे। इस संशोधन से पहले क़ानून में ट्रांसजेंडर पुरुष भी शामिल थे. अब यह समुदाय बाहर हो गया है। इस वजह से ट्रांस पुरुष (ट्रांसमेन) और 'ट्रांसमैस्कुलिन' पहचान को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। '

समर ने इस साल जेंडर संगति सर्जरी कराने का फ़ैसला किया था ताकि वे अपने आपको पुरुष स्वरूप के और क़रीब महसूस कर सकें।

जैसे ही मौजूदा बिल पेश हुआ, समर ने सूरत के उस क्लिनिक में फ़ोन किया, जहां उन्होंने दिसंबर 2024 में हिस्टेरेक्टॉमी यानी गर्भाशय निकालने की सर्जरी करवाई थी। उन्हें अभी कुछ और सर्जरी करवानी हैं। वह बताते हैं, 'मुझे डर लगा कि नए विधेयक से मेरी पहचान पर असर पड़ सकता है। मैंने जल्दी से सर्जरी करवाने का फ़ैसला किया। तो डॉक्टर ने मुझसे मेडिकल सर्टिफ़िकेट मांगा। उन्होंने कहा कि सर्जरी हो जाने के बाद उन्हें मेरी सारी जानकारी के साथ ज़िला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।'

नए बिल में मेडिकल बोर्ड का सर्टिफ़िकेट ज़रूरी बना दिया गया है। पहले के क़ानून के तहत 'सेल्फ आइडेंटिटी' की मान्यता थी। इसमें मेडिकल जांच की ज़रूरत नहीं थी। केवल जीआईडी प्रमाण पत्र और ट्रांसजेंडर व्यक्ति कार्ड दिखा कर कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जेंडर संगति सर्जरी करवा सकता था। दरअसल, बिल में ट्रांस पुरुषों के बारे में चुप्पी कानूनी मान्यता तक सीमित नहीं है। यह उन्हें जेंडर संगति सर्जरी के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त करने से भी रोकता है। एडवोकेट जयना कोठारी बताती हैं, 'इसके लिए संशोधन बिल में एक मेडिकल बोर्ड निर्धारित करने की बात की गई है। क़ानून में दी गई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा के अनुसार बोर्ड इंसान की ट्रांस स्थिति तय करेगा। बिल यह भी अनिवार्य करता है कि इलाज देने वाली मेडिकल संस्था ट्रांस व्यक्तियों की सभी संबंधित जानकारी ज़िला मजिस्ट्रेट को दे। इस प्रावधान ने ट्रांसजेंडर पुरुष समुदाय में भारी डर पैदा कर दिया है। अगर मैं मेडिकल बोर्ड के पास जाता हूं, तो वो मेरी पहचान को नकार देंगे क्योंकि चिकित्सकीय रूप से मेरे शरीर में सभी स्त्री अंग अब भी मौजूद हैं। क्या कोई मेडिकल बोर्ड मेरी उस आत्मा का परीक्षण कर सकता है, जो एक पुरुष की है? जब मेडिकल बोर्ड के सामने कपड़े उतारने की बात आती है तो मेरा 'बॉडी डिस्मॉर्फिया' और बढ़ जाता है।'

'बॉडी डिस्मॉर्फिया' एक मानसिक स्थिति है। इसमें व्यक्ति को अपने शरीर से असहजता महसूस होती है। ट्रांस व्यक्तियों को अक्सर इस मानसिक स्थिति से जूझना पड़ता है।

हम दिल्ली के एनजीओ 'ट्वीट फाउंडेशन' द्वारा संचालित शेल्टर होम 'आसरा' भी गए। यह ट्रांस पुरुषों को आश्रय और सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से आए 19 साल के ट्रांसजेंडर पुरुष अव्यांश द्विवेदी ख़ासतौर पर जेंडर संगति सर्जरी के लिए दिल्ली आए हैं लेकिन बिल ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया है। अव्यांश का दावा है कि जिस मेडिकल संस्था से उन्होंने संपर्क किया, उसने सभी ट्रांस पुरुषों के लिए सर्जरी फिलहाल रोक दी है। आसरा के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ट्रांसजेंडर पुरुष मनवीर यादव कहते हैं, 'संशोधन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि डॉक्टर हमें चिकित्सा सुविधाएं देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ट्रांसजेंडर पुरुष इसकी परिभाषा में शामिल नहीं हैं। जब पहले हमें ऐसा भेदभाव झेलना पड़ता था तो हम जानते थे कि हम डॉक्टरों को क़ानूनी रूप से चुनौती दे सकते हैं लेकिन अब तो यह भी बदल गया है।'

सूरत के एलीगेंस क्लिनिक के डॉ. आशुतोष शाह ने बताया कि डॉक्टरों के बीच भी काफ़ी डर है। इसीलिए वे अभी सर्जरी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि यह बिल दक्षता विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने पेश किया है लेकिन डॉक्टरों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से दिशा-निर्देश मिलते हैं। इन्होंने अभी तक कुछ भी साफ़ नहीं किया है। इससे डॉक्टरों में भारी डर और भ्रम की स्थिति बन गई है और जेंडर संगित सर्जरी पूरी तरह रुक गई है।' साल 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पास होने के बाद जेंडर संगति सर्जरी के लिए एक मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक से जीआईडी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी। अब संशोधन बिल पास होने के बाद यह प्रक्रिया विवादास्पद हो गई है। अब एक मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि कोई 'चिकित्सकीय' और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्ति है या नहीं। इस बीच, मनवीर और ट्रांसजेंडर पुरुष कार्यकर्ता विश्वनाथ मैथिल ने मिल कर ट्रांसजेंडर पुरुषों की पहचान और अधिकारों के लिए इस बिल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन ट्रांसजेंडर पुरुषों ने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी में सरकारी दस्तावेज़ हासिल किया है, उनका क्या होगा?

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

पुलवामा हमले के मास्टर माइंड की पीओके में हत्या

- अज्ञात हमलावर ने हमजा बुरहान को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हमजा बुरहान की पीओके में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गये थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के पुलवामा हमले

के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे उसे पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (पीओके) में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया है। डॉक्टर के नाम से मशहूर हमजा बुरहान पर मुजफ्फराबाद में हमला हुआ था और उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। पुलवामा का रहने वाला बुरहान जिसका असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार है उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान को पीओके के मुजफ्फराबाद के पास एक घने जंगली इलाके में अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं जिससे कई गोलियां लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सूखे की आहट!

सुपर अल-नीनो से डराने वाले संकेत

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के अधिकांश हिस्सों में पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। आने वाले दिनों में इस भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दरअसल, वैज्ञानिकों की मानें तो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली सुपर अल-नीनो आकार ले रहा है, जो 1877 के बाद की सबसे विनाशकारी मौसम संबंधी घटना साबित हो सकता है। इसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अल-नीनो भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून को भी प्रभावित करने वाला है।

भारत में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की आहट

- **तेजी से बढ़ रहा तापमान, हर ओर त्राहिमाम**– देश इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहा है। बुधवार को दिल्ली–एनसीआर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, अहमदाबाद और नागपुर जैसे शहरों में पारा 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, और उत्तर प्रदेश के बांदा में लगातार दूसरे दिन तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। यही नहीं महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे दक्षिणी इलाकों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। भारत के एक बड़े हिस्से में भीषण गर्मी का खतरा बना हुआ है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश के कई हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। इस बीच तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी जारी है।

- **1877 की घटना से भी भयंकर हो सकते हैं हालात**– मौसम विशेषज्ञ इसे प्रशांत महासागर में बन रहे सुपर अल–नीनो से जोड़ रहे हैं। अल नीनो का संबंध दक्षिण–पश्चिम मानसून से है, जिसके कारण मानसून पर संकट बढ़ेगा।
- **हो सकता है भारी नुकसान, भारत पर भी असर**– 1982–83 के अल नीनो के कारण वैश्विक आय में लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, जबकि 1997–98 के सदी के अल–नीनो के कारण वैश्विक स्तर पर अनुमानित 5.7 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। ऐसे में विशेषज्ञ अल–नीनो के असर से भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जता रहे हैं। बता दें कि दक्षिण–पश्चिम मानसून देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 70 प्रतिशत प्रदान करता है। अल–नीनो अगर मजबूत होता है तो यह मानसून को ही प्रभावित करेगा।

स्कूल छोड़ने वालों की पढ़ाई फिर शुरू कराएगी सरकार

सीएम बोले-अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक जुलाई से पहले पूरी कर ली जाए

- **एमपी में शिक्षा घर योजना मंजूर, ड्रॉपआउट छात्रों को दोबारा स्कूल से जोड़ा जाएगा**

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाये। गुरू सांदीपनि के जीवन पर भी रोचक पुस्तक तैयार की जाए। स्कूली शिक्षा में कक्षा 8 से 12 में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के कौशल को कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी एक कार्य योजना तैयार की जाए। निजी विद्यालय खोलने के लिए सामाजिक संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाए। अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक जुलाई से पहले पूरी कर ली जाए। सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूलों में सभी पूर्व तैयारियां कर

ली जाएं। प्रदेश की सभी आंशिक जीर्ण-शीर्ण शालाओं की तत्काल मरम्मत करा ली जाए। सभी स्कूलों में बाउण्ड्री वॉल्स बनाई जाए। एक जुलाई से गुरू पूर्णिमा (29 जुलाई) तक 'शिक्षक वंदना कार्यक्रम', अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार सांदीपनि विद्यालय जैसी अत्याधुनिक शालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर प्रदेश की नींव मजबूत कर रही है। प्रदेश के हर विद्यार्थी तक उत्कृष्ट शैक्षणिक सुविधाएं और संसाधन समय पर पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागीय गतिविधियों में तेजी लाएं और 16 जून से प्रारंभ हो रहे शैक्षणिक सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्कूलों में पूर्व छात्र-छात्रा सम्मेलन कराए जाएं, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो अपने विद्यालय से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, वे उस विद्यालय के विकास-विस्तार में कुछ योगदान भी कर सकेंगे।

शालाओं में दिया जाए व्यावसायिक प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की शालाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी कक्षाओं में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का भी अध्ययन कराया जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए संभव हो तो क्षेत्रीय स्व-सहायता समूहों को भी ऐसी शालाओं और विद्यार्थियों से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को सभी विभागों के विद्यालयों को एक करने की योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस जैसे सामाजिक सेवा कार्य को भी बढ़ावा देने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित करें। विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण, ड्राइविंग लायसेंस कैम्प, प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासकीय स्कूलों से पास आउट विद्यार्थी 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा, रोजगार, कृषि कार्य, पैतृक व्यवसाय, कौशल प्रशिक्षण जैसे किस कार्य/रोजगार में लगे हैं, इसकी ट्रैकिंग भी होनी चाहिए। इससे सरकार के पास हमारे युवाओं का एक डेटाबेस तैयार होगा।

भारत के लिए होर्मुज के बाद नई टेंशन की आहट!

- क्यूबा में मोर्चा खोलकर नया संकट खड़ा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान मिशन फेल हो चुका है। उन्होंने करीब तीन महीने पहले जिस सत्ता परिवर्तन के मंसूबे से ईरान पर हमला बोला था, उसमें उन्हें पूरी तरह से नाकामी मिली है। अब लगता है कि वह इसकी भरपाई क्यूबा को डरा-धमका कर लेना चाहते हैं। लेकिन, अगर अमेरिका ने इस समय क्यूबा को किसी तरह से कंट्रोल में लेने की कोशिश की तो भारत के लिए एक नई टेंशन खड़ी हो सकती है। बुधवार को क्यूबा के स्वतंत्रता दिवस पर जिस तरह से अमेरिका ने वहां के 94 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया,उससे यह बात

निकल रही है कि अमेरिका अब टकराव के लिए तैयार है। जबकि, उसने पहले से ही इस कम्युनिस्ट द्वीप पर तेल नाकेबंदी लगाकर उसे आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर तबाह करने की बीज बो रखी है।

क्यूबा पर कंट्रोल की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप!

तथ्य यह है कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और स्ट्राइक ग्रुप को कैरेबियाई सागर में उतार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद संकेत दिया है कि वह क्यूबा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अमेरिकी साउदर्न कमांड ने भी बुधवार को कंफर्म किया कि अमेरिकी फौज इलाके में तैनात कर दी गई है। अमेरिकी साउदर्न कमांड के पास कैरेबियन और लैटिन अमेरिका में मिलिट्री ऑपरेशन की जिम्मेदारी है। इसने एक्स पोस्ट पर कहा है कि यूएसएस निमित्ज ने अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन पूरे ग्लोब में किया है।

वेनेजुएला का हाल देख और भी डर गया है क्यूबा

पिछले कुछ समय से अमेरिका तरह–तरह से क्यूबा पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटा रहा है। इसमें उस पर तेल से जुड़ी पाबंदियां लगाना, कूटनीतिक दबाव डालना और फौज के नाम पर धमकाना शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हाल ही में एक और दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिस तरह से उनके बेडरूम से रात के समय में सैन्य कार्रवाई कर बंधक बनाया था, उसने क्यूबा के लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

भारत पहले से ही तेल और गैस का संकट झेल रहा

ईरान और अमेरिका–इजरायल के बीच युद्ध और जारी तनाव की वजह से भारत पहले से ही तेल और गैस का संकट झेल रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अगर अमेरिका ने कैरिबियाई सागर में अपनी फौज की तैनाती बढ़ाई तो इससे उस क्षेत्र से वैश्विक स्तर पर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर भी निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत समुद्री बीमा की लागत बढ़ने की आशंका को लेकर है। इससे परोक्ष रूप से ही सही वैश्विक व्यापार पर भी प्रभाव पड़ना तय है। अमेरिकी सेना को ईरान में पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट है कि उसके कम से कम 45 विमान इसमें बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में क्यूबा में नया मोर्चा खोलने पर अमेरिकी मिलिट्री को अपना बहुत बड़ा संसाधन कैरेबियाई सागर की ओर भेजना पड़ेगा। इससे अमेरिका को हिंद–प्रशांत क्षेत्र से अपनी सेना की मौजूदगी कम करनी पड़ सकती है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए भारत और अमेरिका आपसी सहयोग में काम करते हैं। अगर यहां से सैनिकों को कम करना पड़ा, तो भारत पर असर पड़ेगा।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 22 मई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

600 करोड़ की जमीन,500 झुग्गियां और ईद का त्योहार

● मुंबई में बुलडोजर ऐक्शन के दौरान जमकर भड़की हिंसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा हरी झंडी के बाद मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर में पश्चिमी रेलवे द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया है। मंगलवार को शुरू हुआ यह अतिक्रमण विरोधथी अभियान बुधवार को हिंसा के बीच भी जारी रहा। अतिक्रमण हटाने का अभियान भारी सुरक्षा तैनाती के साथ शुरू हुआ है। अधिकारियों ने इलाके में लगभग 400 पुलिसकर्मी, 400 जीआरपी और आरपीएफ कर्मी और लगभग 200 रेलवे अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, गरीब नगर में प्रवेश करने वाले कई रास्तों को सील कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दूसरे दिन यानी बुधवार को भारी हिंसा भड़क उठी। बांद्रा ईस्ट स्काईवॉक के पास एक अवैध धार्मिक स्थल को गिराए जाने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज किया। इस झड़प में 7 पुलिसकर्मियों सहित 13 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने विध्वंस दल पर पत्थर, बर्तन और अन्य वस्तुएं फेंकीं, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया। इस घटना में सात पुलिसकर्मी और छह प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जबकि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। दंगा और सरकारी अधिकारियों पर हमले के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

600 करोड़ रुपए जमीन की अनुमानित लागत- रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 5,200 वर्ग मीटर रेलवे भूमि को खाली कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह अतिक्रमण रेलवे अवसंरचना के खतरनाक रूप से करीब तक फैल गई है, जिसमें हार्बर लाइन की पटरियां और ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट (ओएचई) के खंभे शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कई बहुमंजिला झुग्गी-झोपड़ी संरचनाएं पास के पैदल पुलों की ऊंचाई से भी ऊपर उठ गई हैं, जिससे ट्रेन संचालन और भविष्य में रेलवे विस्तार के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह विध्वंस कार्रवाई सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत 2017 से पहले शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया और 27 नवंबर 2017 को जारी बेदखली आदेशों के आधार पर की गई है।

रेलवे विस्तार-ईद की तैयारियों के बीच कार्रवाई

पश्चिमी रेलवे अतिक्रमण हटाने के बाद बांद्रा स्टेशन के आसपास रेलवे के बुनियादी ढांचे के व्यापक विस्तार करेगा। अधिकारियों ने बताया कि बांद्रा स्टेशन के आसपास की भूमि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेलवे कॉरिडोर और पास के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व्यापारिक जिले के निकट है। कई निवासियों ने दावा किया कि वे दशकों से गरीब नगर में रह रहे हैं और उनके पास मकान कर के कागजात, पानी के कर की रसीदें और बीएमसी द्वारा जारी किए गए अधिकृत बिजली कनेक्शन जैसे नागरिक दस्तावेज हैं। कई निवासी इस बात को लेकर नाराज हैं कि यह तोड़फोड़ की कार्रवाई 27 मई को ईद समारोह से कुछ दिन पहले हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब यह कार्रवाई शुरू हुई तब त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। बीएमसी ने मौका मिलते ही ढहा दिया।

संक्षिप्त समाचार

ईरान जंग पर ट्रम्प-नेतन्याहू में टकराव

● अमेरिका ईरान से डील चाहता है, इजराइल कर रहा इनकार

तेल अवीव/वॉशिंगटन (एजेंसी)। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रम्प फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक,

● **ईरान की मंजूरी से 26 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे-** आईआरजीसी ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में 26 जहाज ईरानी मंजूरी के बाद होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे। इनमें तेल टैंकर और कॉमर्शियल जहाज शामिल थे। कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को बायपास करने वाली नई तेल पाइपलाइन का 50 फीसदी काम पूरा हो चुका है। युद्ध के बाद फुजैराह तेल हब पर ड्रोन हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं।

मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रम्प से कहा कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। सीएनएन के मुताबिक, ट्रम्प ने रविवार को नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है। इस ऑपरेशन को 'ऑपरेशन स्लेजहैमर' नाम दिया जाना था। लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रम्प ने घोषणा कर दी कि मंगलवार के लिए तय हमलों को

थलपति विजय के रुटीन ने उड़ाए अफसरों के होश

10 बजने से पहले पहुंच जाते हैं सचिवालय स्टाफ के लिए भी टाइम तय

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने पद संभालने के बाद से अपनी सख्त समयपालन की आदत से सचिवालय की कार्यसंस्कृति में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री लगातार एक

● **अन्य विभागों को भी जारी किए गए आदेश-** इसके तहत उप सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे उपस्थिति रजिस्टर बंद कर 10.00 बजे से पहले उपस्थिति सारांश कार्यालय अनुभाग को सौंपें ताकि उसे संकलित कर अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय तक भेजा जा सके। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इन नए नियमों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तय समय-सारिणी का पालन कर रहे हैं और सप्ताह के कार्यदिवसों में लगभग सुबह 9.45 से 10.00 बजे के बीच सचिवालय पहुंचते हैं। आमतौर पर शाम 4.30 से 5.00 बजे के बीच आधिकारिक कामकाज पूरा होने के बाद वो कार्यालय छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री की इस दिनचर्या के चलते प्रशासनिक विभागों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं कि अधिकारी और कर्मचारी कार्यदिवस की शुरुआत से पहले ही कार्यालय में उपस्थित और सक्रिय रहें। सबसे पहले जिन विभागों ने इस तरह के निर्देश औपचारिक रूप से जारी किए, उनमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग शामिल है।

मेपकास्ट की कार्यशाला में छात्रों ने विमान डिजाइन और निर्माण की बारिकी समझी

भोपाल। मध्यप्रदेश परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल के अंतर्गत संचालित 'सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग' में दिनांक 18 एवं

19 मई 2026 को दो दिवसीय Aeromodelling Design, Build and Fly कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विद्यालयों से आए लगभग 32 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यार्थियों ने विमान मॉडल के डिजाइन, निर्माण एवं उड़ान से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों को व्यवहारिक एवं गतिविधि आधारित तरीके से समझा। कार्यशाला के दौरान MPCST के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने विद्यार्थियों से संवाद किया तथा उन्हें प्रश्न पूछने की आदत विकसित करने, जिज्ञासु बनने एवं रचनात्मक चिंतन अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि सीखने की प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान एवं अनुभवों के माध्यम से एक-दूसरे की सहायता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बच्चों को नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं टीमवर्क की भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर MPCST के कार्यकारी संचालक डॉ. विवेक कटारे जी एवं संयुक्त परियोजना संचालक डॉ. मनोज राठौर जी भी उपस्थित रहे।

कार्यशाला में विद्यार्थियों ने विभिन्न एयरोमॉडल तैयार किए तथा उनके उड़ान परीक्षण भी किए, जिससे उनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के

● कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ड्रा से 1000 का यात्रियों चयन

आस्था का सबसे बड़ा सफर शुरू होने को तैयार

नई दिल्ली (एजेंसी)। आस्था, रोमांच और हिमालयी सफर का इंतजार अब शुरू हो गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए 1000 श्रद्धालुओं का चयन कंप्यूटर ड्रॉ से किया गया है, जहां इस बार यात्रा पहले से ज्यादा आसान और मोटरेबल रूट के जरिए पूरी होगी।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बुधवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए यात्रियों के चयन हेतु कंप्यूटरीकृत ड्रॉ प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान कुल 1000 श्रद्धालुओं का चयन किया गया, जिन्हें निष्पक्ष, रैंडम और जेंडर-बैलेंस्ड प्रक्रिया के जरिए चुना गया है। सरकार ने कहा कि चयन पूरी तरह कंप्यूटर जनित प्रक्रिया से हुआ, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026

जून महीने में शुरू होगी और अगस्त तक चलेगी।

इस बार यात्रा के लिए कुल 20 बैच बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक बैच में 50 यात्री शामिल होंगे। यात्रियों को लिपुलेख दर्रे और नाथू ला दर्रे के जरिए यात्रा कराई जाएगी। दोनों रूट अब पूरी तरह मोटरेबल हो चुके हैं, जिससे यात्रियों को पहले की तुलना में काफी कम पैदल चलना पड़ेगा।

लिपुलेख और नाथू ला रूट से होगी यात्रा

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यात्रियों के लिए दोनों मार्गों पर सुविधाएं बेहतर की गई हैं। सड़क संपर्क मजबूत होने के कारण यात्रा अब ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक मानी जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि अलग-अलग बैचों और रूट से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक यात्रा वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, ताकि चयनित यात्री अपनी यात्रा की तैयारी समय रहते कर सकें। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के श्रद्धालुओं के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। भगवान शिव के निवास स्थल माने जाने वाले कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आवेदन करते हैं। कोविड महामारी और सीमा संबंधी परिस्थितियों के बाद अब यात्रा के सुचारु संचालन को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा जा रहा है।

गाय को घोषित करें राष्ट्रीय पशु

कुर्बानी बिल्कुल अनुचित

बाबरी मस्जिद केस के पूर्व वादी इकबाल अंसारी की मांग

अयोध्या (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में बकरीद के साथ ही सड़क पर नमाज और गायों की कुर्बानी का मुद्दा खासा गरमाता जा रहा है। गाय की कुर्बानी के मामले को लेकर अब मुस्लिम पक्ष की ओर से भी सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व वादी मो. इकबाल अंसारी ने गाय की कुर्बानी का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हम भारतीय मुसलमान हैं और गाय को गौमाता कहा जाता है। इसलिए मुसलमानों को गाय का सम्मान करना चाहिए। सरकार को इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने योगी सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। सवाल हमारे यहां गाय का है।

कांग्रेस नेता का भी समर्थन

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि अगर गौहत्या से हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत होती हैं, तो मेरा मानना है कि हमें गायों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। हम इस देश में साथ मिलकर रहते हैं और एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। हुसैन दलवाई ने इकबाल अंसारी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। इसलिए, लोगों को गाय का सम्मान करना चाहिए। आप बकरियों की कुर्बानी दे सकते हैं। गायों की कुर्बानी देने की क्या मजबूरी है।

मुसलमानों को दी सीख

इकबाल अंसारी ने कहा कि इस्लाम गौहत्या से मना करता है। इसके बाद भी कुछ सरफिरे लोग हैं जो हमारे देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यह सब काम करते हैं। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि गायों का सम्मान करें और गायों का एहतराम करें। गायों को चारा खिलाएं। गाय की कुर्बानी बिल्कुल जायज नहीं है। गाय का दूध दवा की तरह है। इसलिए इसका सम्मान करें। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। यह हमारी भी मांग है और हमारे मुस्लिम समाज की मांग है। उन्होंने कहा कि जो भी मुसलमान पढ़ा-लिखा है, वह गाय का सम्मान करता है। इकबाल अंसारी ने कड़े स्वर में कहा कि अगर कोई भी चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, अगर वह गौमाता के साथ इस प्रकार का कृत्य करता है तो उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति नहीं करते। हम चाहते हैं कि सभी धर्म का सम्मान हो और गाय का सम्मान हो।

'मेलोडी' केमिस्ट्री पर भारत में मचा सियासी घमासान!

टॉफी डिप्लोमेसी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली यात्रा के दौरान वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी साथ हुई टॉफी डिप्लोमेसी ने भारत में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है।

पीएम मोदी द्वारा मेलोनी भारत की फेमस मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश में विपक्ष ने सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कई आरोप लगाए हैं।

यह लीडरशिप नहीं मजाक है- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया, इकॉनमी का हर पहलू प्रभावित हो रहा है, लेकिन मोदीजी अपना झूठ जारी रखे हुए हैं, नागरिकों को इस गंभीर आर्थिक तूफान का बोझ उठाने के लिए लेक्चर दे रहे हैं। इंडिया की टॉफी टेल जरूर कानों को सुकून देगी! 2013-14 से एक्सपोर्ट में बढ़ोत्तरी है।

बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य

● सीएए लागू, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए दी जमीन

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 19 मई को जारी किया गया। जानकारी गुरुवार को सामने आई। सरकार के आदेश के मुताबिक, यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा (असेंबली) में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान जन गण मन और कवि गुलाम मुस्तफा की अनंत असीम प्रेममय तुमी (बांग्ला गीत) गाया जाता था। अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी।

12 दिनों में बंगाल सरकार के 12 बड़े फैसले

भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने और बाड़ (फेंसिंग) लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 600 एकड़ जमीन 45 दिनों के भीतर दी जाएगी, जिससे सीमा से जुड़ा पुराना विवाद खत्म होगा। सीएए के तहत आने वाले 7 समुदायों और 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों को नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा। पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकेगी। पश्चिम बंगाल सरकार अब केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गई है, जिसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

अफसरों को केंद्रीय ट्रेनिंग पर भेजने की मंजूरी

पुरानी नीति को बदलते हुए अब राज्य के आईएएस, आईपीएस और डब्लूबीपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने राज्य में नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों (जैसे भारतीय न्याय संहिता) को पूरी तरह लागू करने का निर्णय लिया है। ये कानून पुराने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लेंगे, जिन्हें पिछली सरकार ने राज्य में आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया था। साल 2021 की चुनावी हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को सरकारी नौकरी या आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार इन मामलों की दोबारा जांच कराने और पीड़ित परिवारों को पूरी कानूनी सहायता देने के लिए भी तैयार है। मदरसा विभाग और अन्य धर्मों से जुड़ी वित्तीय सहायता वाली योजनाओं को जून महीने से बंद करने का फैसला लिया गया है। सरकार अब बिना किसी भेदभाव के सबके लिए समान योजनाएं चलाएगी। अन्नपूर्णा योजना- महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू होने जा रही है, जिसके तहत उन्हें हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा 1 जून से ही राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर पूरी तरह मुफ्त कर दिया जाएगा। प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए सरकारी बोर्डों, निगमों और आयोगों में मनोनीत किए गए अध्यक्षों और निदेशकों को पद से हटा दिया गया है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी पर रखे गए अफसरों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। सरकार ने गोहत्या से जुड़े 1950 के कानून व हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है।

● **जनगणना को शुरू करने का फैसला-** राज्य में काफी समय से अटकी पड़ी जनगणना को तुरंत शुरू करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जून 2025 के इस आदेश पर पिछली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था। सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आवेदन की उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है।

ईद से पहले

ईदगाह की बदहाल व्यवस्थाओं पर सवाल

● 28 मई को होगी ईदुल अज़हा, पार्किंग-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग

भोपाल। ईदुल अज़हा (बकरीद) को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस वर्ष 28 मई को ईद मनाए जाने की तिथि तय हो चुकी है। जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, शहरभर में बकरा बाजार लगने लगे हैं और मुस्लिम समाज में उत्साह का माहौल है। हालांकि, इसी बीच शहर की ऐतिहासिक ईदगाह और उसके आसपास की व्यवस्थाओं को लेकर चिंता भी सामने आई है। कोमी खिदमतगार हाजी मोहम्मद इमरान हारून ने औकाफ अमला और संबंधित

विभागों से मांग की है कि ईद से पहले ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। उन्होंने कहा कि ईदगाह की गरिमा के अनुरूप यहां सफाई, सुरक्षा और पार्किंग की समुचित व्यवस्था हर साल देखने को नहीं मिलती, जो चिंताजनक है। हाजी इमरान ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के पास करोड़ों का बजट होने के बावजूद ऐतिहासिक ईदगाह और उसकी पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर हजारों नमाजी यहां इकट्ठा होते हैं, ऐसे में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना पूरे समाज के लिए अफसोसजनक है। उन्होंने शहर के रसूखदार लोगों से भी अपील की है कि वे आगे आकर ईदगाह और उसकी पार्किंग के संरक्षण व सुरक्षा में योगदान दें। साथ ही नगर निगम से भी सहयोग की मांग करते हुए कहा कि शहरभर में पानी, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हाजी इमरान ने मुस्लिम समाज से भी अपील की है कि ईदुल अज़हा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और अपने-अपने मोहल्लों में साफ-सफाई बनाए रखें, ताकि त्योहार सौहार्द और जिम्मेदारी के साथ मनाया जा सके।

ओल्ड सेक्रेटिएट में बनेगा नया प्रशासनिक कॉरिडोर

भोपाल में एक जगह होंगे कलेक्टोरेट, कमिश्नर-आईजी दफ्तर, टेंडर जारी

भोपाल। भोपाल के कोहेफिजा स्थित ओल्ड सेक्रेटिएट में ही नया प्रशासनिक कॉरिडोर बनेगा। जिसमें कलेक्टोरेट, कमिश्नर और आईजी कार्यालय होंगे। इसके टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है। हाउसिंग बोर्ड ने मौजूदा कलेक्टोरेट परिसर में ही नए कंपोजिट एडमिनिस्ट्रेटिव हब के निर्माण का आधिकारिक टेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही पर्यावरणीय अड़चनों में फंसा प्रोफेसर कॉलोनी वाला पुराना प्रस्ताव भी समाप्त हो

गया है। अब ओल्ड सेक्रेटिएट परिसर ही भोपाल का नया प्रशासनिक कॉरिडोर बनेगा, जहां कलेक्टोरेट, कमिश्नर और आईजी कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। इस निर्माण के बदले चयनित डेवलपर को पुराने सचिवालय परिसर में 3.36 हेक्टेयर जमीन कंपेंसेटरी लैंड पार्सल (सीएलपी) के रूप में मालिकाना हक के साथ दी जाएगी। इस जमीन का मिक्स लैंड यूज रखा गया है, यानी यहां रेसीडेंशियल और कमर्शियल हाईराइज प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकेंगे। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 217.96 करोड़ रुपए है, जबकि बदले में दी जाने वाली जमीन की कीमत 256.92 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह पूरा मॉडल राज्य सरकार की री-डेंसिफिकेशन नीति के तहत लागू किया जा रहा है, ताकि सरकारी खजाने पर सीधा वित्तीय बोझ न पड़े।

एक परिसर में होंगे तीन बड़े दफ्तर

प्रोजेक्ट के तहत जी+7 कंपोजिट ऑफिस बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें कलेक्टर कार्यालय, संभागायुक्त कार्यालय और आईजी कार्यालय संचालित होंगे। इसके अलावा जी+2 मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी, जिसमें 80 ईसीएस क्षमता रहेगी। परिसर में संप वेल, बिजली सब-स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। डेवलपर को दी जाने वाली जमीन तीन हिस्सों में बांटी है। सीएलपी-1 सबसे बड़ा 2.15 हेक्टेयर का ब्लॉक होगा। 0.63 हेक्टेयर और 0.58 हेक्टेयर के दो अन्य पार्सल भी शामिल किए गए हैं।

भीषण गर्मी और तपन से लोगों का हाल बेहाल

● मोबाइल पर 6 जिलों में हीटवेव का इमरजेंसी का अलर्ट ● खजुराहो में टेम्परेचर रिकॉर्ड 47.4 डिग्री पार तक पहुंचा

भोपाल। मध्य प्रदेश में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। नौतपा शुरू होने से पहले ही कई शहर भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। खजुराहो 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है। तेज धूप और तपन के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। यहां तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि इंसानों के साथ अब जानवर भी गर्मी से बेहाल होने लगे हैं। वन विहार नेशनल पार्क में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। शेर, बाघ और तेंदुओं के हाउस में कूलर, पर्दे और ग्रीन नेट लगाए गए हैं, जबकि बाड़ों में लगातार पानी भरा जा रहा है। वहीं भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सतना, रीवा, मैहर, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर जिलों में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों के मोबाइल फोन पर चेतावनी संदेश भेजकर धूप से बचने, जरूरी सावधानी बरतने और बिना जरूरत बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।

खजुराहो में दोपहर 3.30 बजे 45.4 डिग्री तापमान- खजुराहो में भीषण गर्मी का असर

लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज गर्मी के कारण खजुराहो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम नजर आई। वहीं, गर्मी से राहत के लिए पानी की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखी गई।

मैहर में 43 डिग्री तापमान, दोपहर में सड़कें सूनी- मैहर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार दोपहर 3 बजे तक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक चला गया जिससे जनजीवन प्रभावित नजर आया। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग घरों में रहने को मजबूर दिखे। गर्मी से राहत पाने के लिए गन्ने के जूस के ठेलों पर लोगों की भीड़ उमड़ती रही। वहीं समाज सेवियों ने शहर के कई स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की है। मैहर सिविल अस्पताल, अग्रसेन चौराहा समेत कई जगह राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई है।

रीवा में 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है अधिकतम तापमान- रीवा में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार गुरुवार को शहर में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। मंडला जिले में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी पड़ रही है। बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक था। गुरुवार दोपहर 1 बजे तापमान 42 डिग्री के पार चला गया है।

शाजापुर-गर्म होकर बंद हो जा रहे मोबाइल फोन

शाजापुर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आज सुबह से ही सूरज का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। दोपहर 1 बजे इतनी गर्मी है कि मोबाइल भी हीट मार रहा है। हमने शहर के गर्मी के हालात दिखाने के लिए मोबाइल निकाला और वीडियो शूट करना शुरू किया। कुछ ही मिनट बाद मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद छाया में खड़े होने के बाद मोबाइल सामान्य हुआ, लेकिन दोबारा शूट करने पर फिर से बंद हो गया। मौसम विभाग ने पारे में लगातार बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। यहां के रामप्रसाद सोलंकी ने बताया, आईफोन जैसे मोबाइल भी अधिक गर्म होकर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। कई बार फोन हीट होने के कारण बंद हो जाते हैं या उनकी स्पीड धीमी हो जाती है।

भोपाल के होटल में घुसकर तलाशी का आरोप

● 'लव जिहाद' के शक में पहुंचे कार्यकर्ता, भानु हिंदू समेत 10 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर

भोपाल। भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मारवाड़ी रोड के श्री बालाजी होटल में घुसकर तलाशी लेने के आरोप में पुलिस ने कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों पर केस दर्ज किया है। होटल संचालक राजकुमार वर्मा की शिकायत पर भानू हिन्दू, रावी और अन्य 10 से 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। राजकुमार वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 मई की शाम करीब 4 बजे वे होटल पर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान भानू हिन्दू, रावी और उनके साथ 10 से 15 लोग होटल पहुंचे। सभी लोगों ने होटल कर्मचारियों से कहा कि होटल में एक हिंदू महिला को मुस्लिम युवक लेकर आया है। इसी शक के आधार पर वे होटल की तलाशी लेंगे। होटल कर्मचारी ने जब उनसे तलाशी लेने के अधिकार के बारे में पूछा, तब भी समूह होटल के कमरों की जांच करने लगा। इस दौरान होटल का सामान भी अस्त-व्यस्त कर दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि होटल के खुले कमरों की जांच की गई, लेकिन वहां कोई आपत्तिजनक नहीं मिला। घटना के दौरान आसपास बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए। होटल संचालक राजकुमार वर्मा का कहना है कि इस घटनाक्रम से होटल की छवि और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने पुलिस को होटल के सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आईबीसीए इवेंट का करेंगे शुभारंभ

20 बाइक एवं एक रेस्क्यू ट्रक को झण्डी दिखाकर करेंगे रवाना

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) प्री-समिट इवेंट का 22 मई 2026 को शुभारंभ होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) ऑडिटोरियम, भोपाल में होने वाले इस प्री-समिट इवेन्ट में केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मध्यप्रदेश शासन, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केन्द्रीय मंत्री श्री यादव प्रातः 9:50 पर वन विभाग द्वारा आयोजित 20 बाइक एवं एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन तथा विशेष रूप से बिग कैट संरक्षण के विभिन्न आयामों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के महानिदेशक डॉ. एस.पी. यादव आईबीसीए की गतिविधियों एवं उद्देश्यों पर प्रस्तुति देंगे। साथ ही मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा भारत में चीता पुर्नस्थापन अभियान पर विशेष प्रस्तुति भी दी जाएगी।

आईईसी सामग्री का होगा विमोचन

कार्यक्रम में जैव विविधता एवं संरक्षण से संबंधित अनेक प्रकाशनों और डिजिटल पहलों का विमोचन एवं लोकार्पण किया जाएगा। इनमें डाक टिकट, 'इंडियाज बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2026', नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट तथा एबीएस एंड-टू-एंड वेब पोर्टल शामिल हैं। इसके साथ ही एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, अमरकंटक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट तथा मध्यप्रदेश के पवित्र वनों के संरक्षण पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस आयोजन से जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन तथा वन्य जीव संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही भारत की प्रतिबद्धता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित होगी।

जिलों में एडीएम के पद खाली, युवाओं को चाहिए मौका

राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की पदस्थापना का संतुलन नहीं बना पा रही सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के सीनियर अफसरों को अपर कलेक्टर पद पर पदस्थ करने के मामले में राज्य सरकार संतुलन नहीं बना पा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले से पोस्टिंग का बिगड़ा तालमेल अब तक पटरी पर नहीं आ पाया है। इसका असर यह है कि करीब 20 जिलों में अपर कलेक्टर के पद रिक्त हैं। नियमित अधिकारी की पोस्टिंग नहीं होने से एक ओर जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है तो दूसरी ओर मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अवर सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे युवा अफसरों में गुस्सा भी है कि सरकार उनसे फील्ड का काम नहीं ले रही है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के बड़े जिलों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में दो से तीन अपर कलेक्टर की पदस्थापना की जाती है। यहां

कलेक्टर कार्यालय में इतने पद स्वीकृत भी हैं लेकिन इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में यह पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इसके अलावा छोटे जिलों में भी अपर कलेक्टर के पद पर पोस्टिंग नहीं होने से कलेक्टरों को व्यवस्था संचालन के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपनी पड़ रही है।

एसडीएम कैडर के पद नहीं भरे गए- यही स्थिति संयुक्त कलेक्टर के पदों के मामले में भी है जिन्हें जिले में एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इस कैडर के भी सभी पद नहीं भरे गए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों ने कहा है कि सरकार अधिकारी होने के बाद भी फील्ड में पोस्टिंग न करके इस कैडर के अफसरों की ऊर्जा शक्ति का लाभ नहीं ले पा रही है। जिलों में सीईओ जिला पंचायत का पद भी राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए होता है, वहां सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के मुकाबले युवा आईएएस अफसर अधिक संख्या में तैनात किए हैं।

इन जिलों में खाली हैं अपर कलेक्टर के पद

जिन जिलों में अपर कलेक्टर के पद रिक्त बताए जा रहे हैं उसमें जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, शाजापुर, बड़वानी, बुरहानपुर, ग्वालियर, छतरपुर, निवाड़ी, इंदौर के अलावा आठ अन्य जिले शामिल हैं। इन सभी जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर की पोस्टिंग नहीं किए जाने के कारण कलेक्टरों को प्रभार के सहारे व्यवस्था संचालित करनी पड़ रही है।

नए सिलेक्ट युवाओं की भी मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पोस्टिंग

अभी जो पोस्टिंग है उसमें पीएससी से चुने गए नए युवाओं को भी फील्ड में पदस्थ करने के बजाय मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ रखा है। बताया जाता है कि वर्तमान में अधिकांश युवा अफसर मंत्रालय में अवर सचिव, ओएसडी बनकर फाइलों के निराकरण में लगे हैं। इस कारण उनमें व्यवस्था के प्रति गुस्सा भी है। ऐसे युवा अफसरों का कहना है कि जिलों में डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, अपर कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे कई सीनियर अफसर मंत्रालय में पदस्थ किए जा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कम अनुभवी अफसरों को फील्ड में मौका नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में एसआईआर के कार्य के कारण स्थानांतरण नहीं करने का सरकार का बहाना था और अब जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो भी पदस्थापना नहीं की जा रही है।

संपादकीय

यूएन में अहम सुधार प्रस्ताव

आज जबकि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) अपनी भूमिका और प्रभाव को लेकर निशाने पर है, तब भारत सहित चार बड़े देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के विस्तार और स्थायी सदस्यता को लेकर पेश अहम प्रस्ताव चर्चा में है। हालांकि यूएन के पांच स्थायी देश, जिनके पास वीटो पॉवर है, इस पर शायद ही सहमत हों, लेकिन इस प्रस्ताव से उन पर दबाव तो बनेगा। वैसे भी भारत जैसे कई देश यह कह चुके हैं कि यूएन में अब बदलते वक्त के हिसाब से सुधार होने चाहिए तथा इसे ज्यादा समावेशी और लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए। लिहाजा भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान (जी4 देशों) ने सुरक्षा परिषद में बदलाव को लागू करने के लिए एक रास्ता सुझाया है। इस गुट ने साफ कहा है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की श्रेणी के भीतर कोई और उप-श्रेणी (सब-कैटेगरी) बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती है। जी4 देश चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो नए देश स्थायी सदस्य बनें, उन्हें भी पुराने सदस्यों के बराबर ही अधिकार और शक्तियां मिलें। हालांकि, बातचीत को आगे बढ़ाने और आम सहमति बनाने के लिए जी4 देशों ने एक बड़ा समझौता भी पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत, विस्तारित सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाले नए स्थायी सदस्य शुरुआत में 15 साल तक 'वीटो' पावर (विशेषाधिकार) का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वीटो पावर के इस्तेमाल पर अंतिम फैसला 15 साल की एक लंबी समीक्षा (रिव्यू) अवधि के बाद लिया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सुधार की रुकी हुई प्रक्रिया बिना किसी विवाद के तेजी से आगे बढ़ सके और कोई देश इसमें अड़ंगा न लगाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पर्वथानेनी ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) की बैठक में इस गुट का पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वास्तविक सुधार के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है और अब हम इसके गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं। मौजूदा चर्चा आईजीएन प्रक्रिया की समग्र समीक्षा करने के लिए अच्छा मंच है। इसके जरिए अब तक हुई प्रगति का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है। राजदूत हरीश पर्वथानेनी ने वीटो के सवाल पर जी4 समूह के लचीलेपन को दोहराते हुए कहा कि स्थायी श्रेणी के भीतर किसी भी तरह की कोई उप-श्रेणी नहीं हो सकती है। जी4 गुट का स्पष्ट और अटल रुख यह है कि जो भी नए देश स्थायी सदस्य बनेंगे, उनकी जिम्मेदारियां और दायित्व भी बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए, जैसे अभी मौजूद स्थायी सदस्यों के हैं। रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देने और अपना खुलापन दिखाने के लिए जी4 ने यह खास प्रस्ताव रखा है कि नए स्थायी सदस्य 15 साल की समीक्षा पूरी होने तक वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। जी4 मॉडल के तहत सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या मौजूदा 15 से बढ़ाकर 25 या 26 करने का प्रस्ताव है। इसमें 11 स्थायी सदस्य और 14 या 15 गैर-स्थायी सदस्य होंगे। भारतीय राजदूत ने कहा कि एक एकीकृत मॉडल केवल चर्चा का शुरुआती बिंदु है। आगे की बातचीत लिखित पाठ (टेक्स्ट) के आधार पर ही होनी चाहिए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के इस सबसे शक्तिशाली अंग में केवल पांच वीटो-प्राप्त स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। बाकी 10 सदस्यों को गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत ने आखिरी बार 2021-22 में गैर-स्थायी सदस्य के रूप में काम किया था। जी 4 ने जोर देकर कहा है कि अगर जल्द ही पाठ-आधारित बातचीत शुरू नहीं हुई, तो सुधारों में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो पाएगी।

नजरिया

वेद विलास उनियाल
(वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक)

हिमंता का असम अब किस राह पर

असम के विधानसभा चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए केवल इस बात के लिए अहमियत नहीं रखते कि यहां तीसरी बार कमल खिला है। बीजेपी के लिए असम चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी अहमियत रखते हैं और पूर्वोत्तर भारत में अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए भी इसका महत्व है। असम में जिस प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल की है उसमें बीजेपी की उन नीतियों मुद्दों को बल मिल रहा है जिसे वह बड़े फलक में सामने रख रही है। फिर वह चाहे एसआईआर का मामला हो, घुसपैठ के खिलाफ रणनीति हो या फिर राष्ट्रीयता का बोध कराना हो।

इस बार के चुनाव में बीजेपी ने असम के विकास के साथ कुछ और पहलुओं पर ही जनादेश मांगा था। सीएम हिमंता को असम की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर बहुत सी अपेक्षाएं रखी। असम के विकास के साथ सुरक्षा के पहलू अहम है। घुसपैठ के खिलाफ यह खुला मतदान रहा। हिंमता को पड़ोसी राज्यों से भी तारतम्य बनाए रखना है। असम के सुदूर क्षेत्रों का विकास अपेक्षित है। साथ ही हिंसाग्रस्त क्षेत्रों पर गहरी नजर रखनी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने असम की सत्ता को पाने के लिए असम सम्मिलित मोर्चा बनाकर राइजोर दल, असम जातीय परिषद और लेफ्ट पार्टियों को साथ लिया। असम में तीन गोगोई कांग्रेस के गौरव गोगोई, राइजोर दल करे अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद के लुरिन ज्योति गोगोई ने प्रभावी मोर्चा बनाया, लेकिन वह हिमंता बिस्वा के चक्रव्यूह को नहीं भेद सके।

असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की राजनीतिक आभा के साए में ही हिमंता बिस्वा की सियासत भी आगे बढ़ी। तरुण गोगोई की तुलना में उनके बेटे गौरव गोगोई अपनी उम्र और तजुर्बे में कमजोर पड़े। लेकिन, असम की सियासत में वह अपने मुद्दों को धार नहीं दे सके। खासकर ऊपरी असम में भी कांग्रेस के लिए बड़ा आधार नहीं बना सके। कांग्रेस को लगता था कि असम जातीय परिषद और राइजोर दल को साथ लेकर वह जिस छह घटकों वाले आल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट को लेकर चुनावी रण में गए हैं उससे नतीजों के पक्ष में होने का विश्वास बन रहा था। असम में कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों से अपेक्षित मदद नहीं मिली। हालांकि कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंबी पदयात्रा करके चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की थी। बीजेपी के संगठित चुनावी अभियान के सामने कांग्रेस का प्रचार अभियान रफ्तार नहीं पकड़ा। कांग्रेस की दिक्कतें तब और बढ़ी जब पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने भी चुनाव से ठीक पहले पाला बदला।

हिमंता बिस्वा उन नेताओं में हैं जिनकी सियासी पृष्ठभूमि आरएसएस या जनसंघ से जुड़ी नहीं है। लेकिन 2015 में कांग्रेस छोड़कर वह बीजेपी में आकर उसकी धारा में इतने समरस हो गए कि आज हिंदुत्व सनातन के फायरब्रांड नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। कांग्रेस में उनका अपना वर्चस्व था। लेकिन नेतृत्व से संवाद में कमी होने की बात कहकर उन्होंने 2015 में कांग्रेस को छोड़ा था। हालांकि इसके पीछे तरुण गोगोई से मतभेद उभरना बड़ा कारण बना। हिमंता बिस्वा ने जब कांग्रेस को छोड़ा था तब वह पार्टी में दूसरे नंबर की अहमियत रखते थे। 2011 के चुनाव के बाद उन्हें आभास हुआ कि तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को राजनीति में आगे बढा रहे हैं। हिमंता बिस्वा का कहना था कि राज्य में पार्टी के

अंदरुनी हालात को लेकर जब उन्हें शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाही तो उन्हें अवसर नहीं मिला। बीजेपी में शामिल होकर वह नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक के रूप में उभरे।

इस बात भी देखा गया कि हिमंता के कांग्रेस से चले जाने पर कांग्रेस ने असम ही नहीं उत्तर पूर्व के राज्यों को भी खोया। वहीं हिमंता ने बीजेपी को ऐसे राज्यों में विस्तार दे दिया जहां उसकी पहुंच नहीं थी। आज नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है। असम का शासन संभालने के बाद हिमंता बिस्वा ने कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक सुधार किए। खासकर उन्होंने संवेदनशील मुद्दों पर अपनी स्पष्टता रखी। हिमंता के शासन को बड़े बदलाव के दौर के रूप में देखा गया। 2025-2026 में असम के विकास की दर 13% रही। केंद्र के सहयोग से भारत सरकार असम और उल्फा के एक बड़े गुट के बीच जो ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ उसका श्रेय हिमंता बिस्वा को मिला।

यही नहीं हिमंता के कार्यकाल में कार्बी बोडो दिमासा जैसे जातीय समूहों के साथ शांति समझौते किए गए। असम के हालात धीरे-धीरे पटरी पर आते रहे। हिमंता की लोगों से जुड़ाव और सीधे संवाद की शैली लोगों को पसंद आई। हिमंता सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर पड़ोसी राज्य मेघालय और अरुणाचल के पुराने सीमा विवाद भी सुलझाए। राज्य में कनेक्टिविटी पर बहुत फोकस किया गया। असम के ब्रह्मपुत्र में कई छोटे बड़े पुल बने। जागीरोड में टाटा ग्रुप के बडे सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना हिमंता सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी गई। हिमंता सरकार ने ओरनोदोई, निजुत मोइना मिशन वसुंधरा जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई।

हिमंता सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया। असम में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी की प्रभावी रणनीति रही। विकास और सांस्कृतिक अस्मिता के साथ साथ राष्ट्रीय सरोकारों पर बीजेपी ने फोकस किया। असम में मतदाताओं को यह बताने की कोशिश की गई कि अवैध घुसपैठ को रोकने सरकार सख्त नियम लाई है।गौ सीएम हिमंता बिस्वा ने पिछले कुछ समय से अपनी सभाओं में मियां मुस्लिम शब्द का जिक्र करना शुरू कर दिया था। असम में मियां शब्द का इस्तेमाल बांग्लादेश के बांग्ला बोलने वाले मुस्लिमों के लिए किया जाता रहा है। हिमंता खुलकर कहते रहे कि मियां लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बात को प्रमुखता से कहा गया कि घुसपैठ रोकना केवल बीजेपी के पक्ष में है। वहीं यूसीसी को लागू करने का भरोसा दिया गया।

महिला वोट बैंक और युवाओं को साधने के लिए हिमंता बिस्वा ने राज्य भर में अपने चुनाव प्रचार को गति दी। बीजेपी ने राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दलों के साथ संतुलन बिठाया। असम की 126 सीटों में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ी। असम गण परिषद को 26 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को प्रमुखता देकर 15 सीटें दी। रभा हासोंग संयुक्त मंच को भी एक सीट दी गई। बीजेपी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदला। गौरतलब है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र में बीजेपी ने केवल चार सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। बीजेपी का पूरा प्रचार अभियान भी सुनियोजित था। असम की अस्मिता संस्कृति से अपने जुड़ाव के लिए पीएम ने भूपेन हजारिका, चाय बागान श्रमिक लोकपर्व बिहू से अपने जुड़ाव को बताने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कई रैलियों रोड शो के जरिए असम के जनमानस को प्रभावित करने की कोशिश की। वहीं अमित शाह ने भी असम में आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को उठाया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने राज्य के विकास के साथ साथ हिंदू गौरव और संस्कृति को अपने चुनावी भाषणों का आधार बताया। असम में कमल खिलाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिमंता की तरह सनातन का उद्घोष किया।

विश्व राजनीति

ममता कुशवाहा
लेखक शिक्षक हैं।

शक्ति संघर्ष और शांति की संभावना

इक्कीसवीं सदी का वैश्विक परिदृश्य केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं रह गया है, बल्कि यह शक्ति, प्रभुत्व, तकनीक, सैन्य संतुलन और कूटनीतिक प्रभाव की बहुआयामी लड़ाई में बदल चुका है। इस बदलती हुई दुनिया में अमेरिका और चीन दो ऐसे ध्रुव बनकर उभरे हैं जिनकी नीतियाँ केवल उनके नागरिकों को ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की यात्रा की, तब पूरी दुनिया की निगाहें बीजिंग पर टिक गईं। यह यात्रा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उस तनावपूर्ण दौर में संवाद की एक कोशिश थी जहाँ व्यापार युद्ध, ताइवान संकट, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़ा संघर्ष वैश्विक स्थिरता को चुनौती दे रहे थे। दुनिया इस समय बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की राजनीति को अस्थिर किया, वहीं ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तल्खी ने पश्चिम एशिया को विस्फोटक बना दिया। ऐसे समय में चीन और अमेरिका जैसे महाशक्तियों के बीच संवाद का हर प्रयास विश्व राजनीति में आशा की एक किरण माना जाता है। ट्रंप की यह यात्रा इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि यह केवल दो नेताओं की मुलाकात नहीं, बल्कि दो वैचारिक व्यवस्थाओं के बीच संतुलन साधने का प्रयास थी।

व्यापार युद्ध की पुरानी विरासत

अमेरिका और चीन के संबंधों में तनाव की जड़ें नई नहीं हैं। वर्ष 2018 में ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ा था। अमेरिका का आरोप था कि चीन अनुचित व्यापारिक नीतियों, बौद्धिक संपदा की चोरी और सरकारी संरक्षण के माध्यम से वैश्विक बाजार में असंतुलन पैदा कर रहा है। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाए। परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच आर्थिक अविश्वास गहराता चला गया। इस व्यापार युद्ध ने केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं किया, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी झकझोर दिया। दुनियाभर की कंपनियाँ असमंजस में पड़ गईं कि वे किस पक्ष के साथ खड़ी हों। तकनीकी क्षेत्र में तो यह संघर्ष और भी तीखा हो गया। अमेरिका ने चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, विशेषकर सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी तकनीकों पर नियंत्रण बढ़ाया। चीन ने इसे अपनी आर्थिक संप्रभुता पर हमला माना। ट्रंप की चीन यात्रा इसी पुराने तनाव को कम करने की कोशिश थी। दोनों देशों ने यह महसूस किया कि लगातार बढ़ती शत्रुता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य केवल समझौते करना नहीं था, बल्कि उस टूटे हुए विश्वास को पुनर्जीवित करना भी था जो वर्षों के टकराव में लगभग समाप्त हो चुका था।

ईरान संकट और कूटनीतिक दबाव

ट्रंप की चीन यात्रा ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था। होर्मुज जलडमरूमध्य में संघर्ष की आशंका बढ़ रही थी और तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा रहा था। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ इस संकट से चिंतित थीं क्योंकि ऊर्जा बाजार में अस्थिरता वैश्विक मंदी को जन्म दे सकती थी।चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है, इस संकट से सीधे प्रभावित हो सकता था। इसलिए बीजिंग चाहता था कि पश्चिम एशिया में स्थिरता बनी रहे। दूसरी ओर अमेरिका भी जानता था कि यदि चीन का सहयोग नहीं मिला तो ईरान पर दबाव बनाना कठिन होगा। यही कारण था कि ट्रंप ने चीन के साथ संवाद को प्राथमिकता दी।

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चीन ने अमेरिका को संयम बरतने की सलाह दी, जबकि अमेरिका ने चीन से अपेक्षा की कि वह ईरान पर प्रभाव डालकर क्षेत्रीय तनाव कम करने में मदद करे। यह कूटनीतिक संतुलन अत्यंत जटिल था क्योंकि चीन ईरान का आर्थिक सहयोगी भी है और अमेरिका का रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी। फिर भी दोनों देशों ने यह समझा कि यदि पश्चिम एशिया में आग भड़की, तो उसकी लपटें वैश्विक अर्थव्यवस्था को झुलसा देंगी।

ताइवान प्रश्न की गंभीर चुनौती

अमेरिका-चीन संबंधों का सबसे संवेदनशील मुद्दा ताइवान है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता रहा है। यही कारण है कि ताइवान जलडमरूमध्य आज दुनिया के सबसे

खतरनाक भू-राजनीतिक क्षेत्रों में गिना जाता है। चीन की दृष्टि में अमेरिका ताइवान के माध्यम से उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं अमेरिका का तर्क है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहा है। इस वैचारिक संघर्ष ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है। ट्रंप की यात्रा के दौरान भी यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में रहा।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पष्ट संकेत दिए कि ताइवान के प्रश्न पर चीन किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि उसने ताइवान को सैन्य सहायता बढ़ाई तो संबंध और खराब हो सकते हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने सावधानीपूर्वक संतुलित भाषा अपनाई। उन्होंने सीधे टकराव से बचते हुए संवाद जारी रखने पर जोर दिया। ताइवान का प्रश्न केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुका है। यदि इस मुद्दे पर संघर्ष बढ़ता है तो उसका प्रभाव सम्पूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर पड़ेगा। इसलिए इस यात्रा में स्थिरता की खोज का सबसे बड़ा अर्थ ताइवान संकट को नियंत्रित करना भी था।

तकनीकी प्रतिस्पर्धा का नया युद्ध

आज की दुनिया में शक्ति केवल सैन्य क्षमता से निर्धारित नहीं होती, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता भी महाशक्ति बनने का आधार बन चुकी है। अमेरिका और चीन के बीच सबसे तीखी प्रतिस्पर्धा तकनीक के क्षेत्र में दिखाई देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, 5 प्रतिशत नेटवर्क और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में दोनों देश एक-दूसरे को पीछे छोड़ने की दौड़ में लगे हैं। अमेरिका ने चीन पर उन्नत चिप्स और तकनीकी उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए। उसका उद्देश्य चीन की तकनीकी प्रगति को सीमित करना था। वहीं चीन ने इसे आर्थिक युद्ध बताया और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए। ट्रंप की यात्रा में अमेरिकी उद्योगपतियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि व्यापार और तकनीक दोनों इस वार्ता के केंद्र में थे।

चीन चाहता था कि अमेरिका तकनीकी प्रतिबंधों में नरमी लाए ताकि उसकी कंपनियों को वैश्विक बाजार में अवसर मिल सके। वहीं अमेरिका चाहता था कि चीन अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार खोले। यह संबंध विरोधाभासों से भरा हुआ है। दोनों एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हैं और आर्थिक साझेदार भी। तकनीकी युद्ध का प्रभाव केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है। यह आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संरचना को निर्धारित करेगा। इसलिए इस यात्रा में तकनीकी सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों की छाया स्पष्ट दिखाई दी।

व्यक्तिगत संबंधों की कूटनीति

विश्व राजनीति में कई बार नेताओं के व्यक्तिगत संबंध भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच संबंधों को लेकर हमेशा जिज्ञासा बनी रही है। दोनों नेताओं की शैली अलग है, लेकिन दोनों मजबूत राष्ट्रवादी छवि वाले नेता माने जाते हैं। इस यात्रा में औपचारिक बैठकों के अतिरिक्त अनौपचारिक वार्ताओं पर भी विशेष जोर दिया गया। बीजिंग के सांस्कृतिक स्थलों पर साथ घूमना, भोज में शामिल होना और निजी स्तर पर विचार साझा करना इस बात का संकेत था कि दोनों देश तनाव के बावजूद संवाद का पुल बनाए रखना चाहते हैं। कूटनीति केवल दस्तावेजों और समझौतों से नहीं चलती; उसमें विश्वास और संवाद का भी महत्व होता है। ट्रंप और शी के बीच हुई मुलाकातों ने कम-से-कम इतना तो स्पष्ट कर दिया कि दोनों देश प्रत्यक्ष टकराव से बचना चाहते हैं। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कटुता इतनी बढ़ गई थी कि संवाद लगभग ठप पड़ चुका था। हालाँकि व्यक्तिगत संबंधों की यह गर्माहट स्थायी समाधान नहीं दे सकती, लेकिन यह भविष्य के लिए संवाद का वातावरण अवश्य तैयार करती है। विश्व राजनीति में यह छोटी-सी नरमी भी कई बार बड़े संकटों को टालने में सहायक बन जाती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इसलिए उनके संबंधों में आने वाला हर उतार-चढ़ाव वैश्विक बाजारों को प्रभावित करता है। ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान दुनिया भर के निवेशक इस बात पर नजर बनाए हुए थे कि क्या दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम होगा। यदि अमेरिका और चीन सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल सकती है। ऊर्जा बाजार, तकनीकी उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सभी इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन यदि प्रतिस्पर्धा और बढ़ती है तो दुनिया नए आर्थिक विभाजन की ओर बढ़ सकती है।

इस यात्रा ने यह संकेत अवश्य दिया कि दोनों देश आर्थिक संबंध पूरी तरह तोड़ने की स्थिति में नहीं हैं। अमेरिका को चीन का विशाल बाजार चाहिए और चीन को अमेरिकी तकनीक तथा निवेश की आवश्यकता है। यह परस्पर निर्भरता दोनों देशों को संवाद के लिए बाध्य करती है। हालाँकि भविष्य आसान नहीं है। आर्थिक हितों और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना कठिन होगा। फिर भी यह यात्रा इस बात का प्रमाण थी कि महाशक्तियाँ अंततः संवाद की मेज पर लौटने को विवश होती हैं क्योंकि वैश्विक स्थिरता उनके अपने हित में भी है।

ट्रंप की चीन यात्रा ने दुनिया को यह संदेश दिया कि प्रतिस्पर्धा और सहयोग एक साथ चल सकते हैं। यह यात्रा कोई चमत्कारी समाधान लेकर नहीं आई, लेकिन इसने संवाद की संभावनाओं को जीवित रखा। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भविष्य में अमेरिका और चीन के संबंध किस दिशा में जाएंगे, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। ताइवान संकट, तकनीकी प्रतिबंध, व्यापारिक नीतियाँ और पश्चिम एशिया की राजनीति इन संबंधों को प्रभावित करती रहेंगी। यदि दोनों देश केवल शक्ति प्रदर्शन में उलझे रहे तो विश्व व्यवस्था अस्थिर हो सकती है। लेकिन यदि वे प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग का संतुलन बनाए रखते हैं, तो वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता की संभावनाएँ मजबूत होंगी। आज दुनिया को संघर्ष नहीं, बल्कि संवाद की आवश्यकता है। परमाणु हथियारों और तकनीकी युद्ध के इस युग में महाशक्तियों के बीच टकराव मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए अमेरिका और चीन के बीच स्थिरता की खोज केवल दो देशों का विषय नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। बीजिंग की इस यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि दुनिया चाहे कितनी भी विभाजित क्यों न हो जाए, अंततः संवाद ही वह सेतु है जो अविश्वास की खाइयों को पाट सकता है। शायद यही इस यात्रा का सबसे गहरा और स्थायी संदेश भी है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज
लेखक स्तंभकार हैं।

संत साध्वियों का पैदल विहार निरापद हो

हाल ही में रीवा के नजदीक सड़क दुर्घटना में जैन साध्वियों का दुखद निधन हो गया। जैन संत परंपरा में विभिन्न संत एवं साध्वियां पैदल विहार करते हुए ही गंतव्य तक पहुंचते हैं। इस घटना ने समूचे जैन समाज को झकझोर कर रख दिया है। सड़कों पर अंधाधुंध गति से दौड़ते वाहन की चपेट में कौन कब आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने को तो तमाम तरह के यातायात के नियम है और वाहन चालकों के लिए बहुत कुछ कानून कायदे भी निश्चित है। लेकिन आए दिन होती दुर्घटनाएं सड़क मार्ग को लगातार खतरनाक घोषित करती जा रही है। यहां तक कि पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं रह गया है।

इसका मुख्य कारण यही है कि वाहन चालन के अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व वाहन चालन के प्रति परिपक्वता को ईमानदारी से नहीं मापा जाता। परिणाम स्वरूप लापरवाही भरे अंदाज में वाहन चालन निर्दोषों की जान लेता रहा है। इसके अतिरिक्त नशीले पदार्थों का सेवन करने के उपरांत वाहन चालन के चलते भी सड़क मार्ग लगातार असुरक्षित होता जा रहा है। बीते दौर में भी पैदल विहार कर रहे संत साध्वियों के साथ सड़क मार्ग पर अनेक दुर्घटनाएं हुई है। यह निश्चित है कि व्यक्ति जब आहत होता है, विशेष कर परिवार पर गाज गिरती है। लेकिन जब संत साध्वियां आहत होती है, समूचे समाज के लिए यह एक गंभीर क्षति बन जाती है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि संत साध्वियों को सकल समाज की अनुपम धरोहर के रूप में देखा जाता है। जो अपने आचरण और व्यवहार में धर्म धारण कर धर्म की प्रभावना के केंद्रबिंदु हुआ करते है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाएं तो स्वस्थ समाज की संरचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा करता है। यही नहीं अपितु देश प्रदेश में कानून और व्यवस्था के परिपालन की दिशा में परोक्ष रूप से भी संत साध्वियों का अहम योगदान रहा करता है। संत समुदाय द्वारा अपने मुखारविंद से समय-समय पर धर्म के मर्म की व्याख्या की जाती है। जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि संबंधित समाज हर एक दृष्टि से स्वस्थ समाज का आकार ग्रहण करता है।

एक अर्थ में इस बात को कुछ यूं भी कहा जा सकता है कि वह संत समुदाय ही है जिनके आचरण और व्यवहार में विशुद्ध धर्म होता है और उनकी जिव्हा पर सरस्वती का वास हुआ करता है। व्यवहार में देखा गया है कि विभिन्न धर्म संप्रदाय के संत साध्वियों द्वारा मनोविकारों को त्यागने का उपदेश दिया जाता है। यह केवल और केवल उपदेश मात्र नहीं होता, दरअसल इसके पीछे संत साध्वियों की त्याग और तपस्या का प्रभाव भी रहता है। जिसके चलते संतो के अमृत प्रवचन को सकल समाज अपने व्यावहारिक जीवन में अंगीकार करने का संकल्प लेता है। इससे समाज में सदाचार और परोपकार की भावना विकसित होती है।

उपरोक्त दृष्टिकोण के आधार पर यह तथ्य स्थापित होता है कि सामाजिक परिवेश में संत साध्वियों के समूचे जीवन का एक-एक पल कितना बेशकीमती है। यह निश्चित है कि संत साध्वियों की समाज में उपस्थिति के चलते कहीं से कहीं तक कोई समाज या समाज का कोई व्यक्ति अनैतिक नहीं हो सकता। एक प्रकार से संत साध्वियों की अमृतमयी धर्म वाणी मानव मात्र के लिए मानव भव को सार्थक सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया करती है। इन तमाम संदर्भों में यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि संत साध्वियों का त्यागमयी जीवन सकल समाज के इहलोक एवं परलोक संवारने में प्रबल रूप से सहायक सिद्ध होता है।

बेहतर हो यदि शासन प्रशासन संत साध्वियों के पैदल विहार को हर एक दृष्टि से निरापद रखने विषयक आवश्यक व्यवस्था को मूर्त रूप देवें। साथ ही तमाम वाहन चालकों को पैदल यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सावधानी बरतने का सख्त दिशा निर्देश भी जारी करें। यातायात के तमाम नियम कानून कायदों के परिपालन के प्रति आम नागरिकों में जिम्मेदारी के भाव जागृत करते हुए आम नागरिकों के जान माल की सुरक्षा भी निश्चित करें।

मुद्दा

ऋतुपर्ण दवे

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

प्रतिभाशालियों के हौसले तोड़ता रोज-रोज का पेपर लीक

महज एक बयान जारी कर नौ दिन बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल कोर्सों में दाखिले खातिर होने वाली नीट-यूजी की परीक्षा रद्द कर दी। वजह बताई गई कि एजेंसी को 7 मई को एक व्हिसलब्लोअर ने जानकारी दी कि एक 'गेस पेपर' का पीडीएफ़ व्हाट्सऐप पर सर्कुलेट किया गया था, जिसमें वास्तविक नीट परीक्षा जैसे ही प्रश्न थे। एनटीए के महानिदेशक ने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह का उल्लंघन हमारी ज़ीरो-टॉलरेंस नीति के खिलाफ है और इससे उन 22 लाख छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है जिन्होंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी। बयान के लब्बोलुआब में नपे-तुले शब्दों से अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूर पापड़ बेले गए। लेकिन अब उन लाखों बच्चों का क्या होगा जिन्हें लीक पेपर से कोई वास्ता नहीं था, पेपर अच्छा गया था लेकिन, चयन तय था, लेकिन सपने एक झटके में टूट गए! क्या एनटीए को भान होगा कि बच्चों के कोमल मनोमस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा? जब परीक्षा के पहले ही पीडीएफ बिके, सोशल मीडिया पर वायरल संदेश और सौदेबाजी की बातें हो रहीं थीं तब सारी एजेंसियों के कान में तेल पड़ा था? परीक्षा कोई भी हो, उसकी पवित्रता और निष्पक्षता का ध्यान रखने की गुरुतर जिम्मेदारी उन्हें संचालित करने वालों की होती है।

भारत में कुछ पेपर लीक बहुत ही सुर्खियों, विवादों और चर्चाओं में रहे हैं। ऐसे कुछ मामले आज भी लोगों को भुलाए नहीं भूलते। इनमें मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) का 2013 का मामला काफी चर्चित है। इसमें नकली परीक्षार्थी (सॉल्वर) दूसरों की जगह परीक्षा में सम्मिलित हुए। लंबी रकम देकर इस तरह नौकरियां में जाने का रास्ता भी बना था लेकिन पकड़े गए। मामले में कई आरोपियों सहित जाँच एजेंसियों के लोगों की संदिग्ध मौतें भी हुईं। तब पूरा मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए भी गले की हड्डी बना। आरोप-प्रत्यारोपों की झड़ी लगी लेकिन सभी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। एक अन्य मामला कर्मचारी चयन आयोग का सामने आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रणाली को दूषित बता दिया। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) 2017 परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो गया। सीबीआई जांच में पता चला कि कुछ परीक्षा केंद्रों के सुपरवाइजर्स ने अभ्यर्थियों को रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए बाहरी मदद दिलवाई थी। 2022 में रेलवे भर्ती विवाद में सवा करोड़ युवाओं का सड़कों पर उबाल दिखा जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट पर आपत्ति उठाई। 2024 में यूजीसी नेट की परीक्षा दूसरे ही दिन रद्द कर दी गई जिसमें 9 लाख प्रतिभागियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया जो पीएचडी करने और प्रोफेसर बनने का सपना संजोए हुए थे। बहुचर्चित नीट-

2024 में 67 छात्रों का 720 अंक ही अर्जित करना सुर्खियों में रहा। इसमें झारखण्ड के एक प्रिन्सपल और वाइस प्रिंसिपल ने पर्चा चुराकर लाखों में बेचा था। जिससे सभी के समान अंक आए और मामले ने तूल पकड़ा।

आखिर इतनी जिम्मेदार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना न केवल एनटीए बल्कि उन सारी छोटी-बड़ी उन एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल है जिनके कंधों पर परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता का बोझ है। सवाल यह भी है कि अब तक देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक हुआ? महज प्रिलिम परीक्षा के दौरान 1992 में इलाहाबाद केंद्र पर पेपर लीक होने की शिकायत आई थीजिस पर संसद में बहस हुई थी। सीबीआई जांच में भी यह सिर्फ एक इनविजिलेटर द्वारा पेपर कॉपी करने का मामला निकलान कि लीक का।

आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। इसी बार अब तक कई परीक्षार्थियों ने आत्मघाती कदम उठा लिया है। यह बहुत दुखद है। इसे कौन समझेगा? किस पर बच्चों के कोमल मन को झकझोरने और उन्हें ना समझी में बुरे कदम उठाने का आरोप लगेगा? बहुत ही दुखद है मेहनत के बाद इस तरह की घटनाएँ जहाँ रिवाज बन गई हैं वहीं कई प्रतिभाशाली अपने जीवन को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। पिछले 12-13 वर्षों के छोटे-बड़े मामले देखें तो लगभग सैकड़ा पार हो चुका है। तकरीबन दो करोड़ छात्रों के भविष्य पर हर वर्ष असर पड़ता है। कई उम्र की सीमा लांघ चुके होते हैं तो कई का मनोबल टूटता और बेहतर करने के बजाए अवसाद का शिकार हो जाते हैं जीवन से हाथ धो लेते हैं। उधर एजेंसियां ईमानदारी के नाम पर खुद को कटघरे में पाकर पेपर ही कैंसल कर, दोबारा कराने का आदेश देकर बरी और ईमानदार हो जाती हैं। इधर मामले बनते हैं और अपराधी कटघरे में भी पहुंचते हैं लेकिन अनेकों बार देखने में आया कि निश्चित समय-सीमा में चार्ज शीट दाखिला में देरी से वो भी बाहर आकर दोबारा अपने पुराने कार्यों मे संलग्न हो जाते हैं।

पेपर लीक को लेकर सरकार को सख्त होना पड़ेगा। कहने को तो कई आरोपी अब तक गिरफ्त मे आ चुके हैं। लेकिन इसका हल ढूंढना ही होगा, संसद में बहस करनी होगी, कठोरतम व्यवस्था व प्रभावी कानून बनाने होंगे ताकि लोग पेपर लीक करने या कराने के नाम से ही थर्राने लगे और इस बारे में सोचना ही बंद कर दें। इसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) को रोल मॉडल मान इससे सीख लेनी चाहिए। परीक्षाओं की पवित्रता की गारंटी हुक्मरानों और अफसरों को लेनी ही होगी ताकि प्रतिभाशालियों का हौसला बार-बार न टूटे और विचलित भी न हों।

सामयिक

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

मीठी चॉकलेट की कड़वी दास्तान

इन दिनों चॉकलेट चर्चा में है। हाल ही का एक वाकया गत दिनों काफी चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इटली प्रवास के अवसर पर वहां की पीएम को मेलोडी नामक चॉकलेट्स का पैकेट भेंट किया। इस खास कूटनीतिक अंदाज के इस दिलचस्प मुलाकात का वीडियो खुद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में मेलोनी बेहद खुश नजर आ रही हैं और कैमरे के सामने टॉफी का पैकेट दिखाते हुए मुस्कुराकर कह रही हैं-'पीएम मोदी हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं!' बहरहाल, दो देशों के बीच की कूटनीति और स्नेह, सद्भाव के मधुर और दिलकश प्रसंग से अलग मन को उद्वेलित करने वाला एक प्रकरण अवश्य यहां रेखांकित किये जाने योग्य होगा। दरअसल, एक यूट्यूबर और विश्वयात्री ने जब पश्चिम अफ्रीका के आईवरी कोस्ट (Ivory Coast) में कोको के बाग का भ्रमण करते हुए वहां काम करते मजदूर किसानों से पूछा कि क्या उन्होंने कोको से बनने वाली चॉकलेट का जायका लिया है तो उत्तर पाकर अचम्भा हुआ। सचमुच यह दिल को छू लेने वाली और हैरान करने वाली हकीकत है कि एक ऐसा देश भी है जो कोको का उत्पादन तो करता है लेकिन जहां के उत्पादक मजदूरों ने चाकलेट का स्वाद तक नहीं लिया।

चॉकलेट आज दुनिया की सबसे लोकप्रिय खाद्य वस्तुओं में से एक है, इसकी यात्रा हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताओं से शुरू होकर आधुनिक उद्योग तक पहुँची है। इसका इतिहास केवल स्वाद का नहीं, बल्कि संस्कृति, व्यापार, विज्ञान और मानव सभ्यता के विकास का भी इतिहास है।पश्चिमी अफ्रीका का यह आईवरी कोस्ट (Ivory Coast) छोटा सा देश दुनिया के कुल कोको (Cocoa) का लगभग 40% से अधिक हिस्सा अकेले पैदा करता है। ट्रेवलर यूट्यूबरों के पहले भी कुछ डच पत्रकारों ने यहाँ के एक सुदूर गाँव के किसानों का एक वीडियो बनाया था, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। दशकों से कोको उगा रहे उन मजदूरों को यह तक नहीं मालूम था कि उनके इन कड़वे बीजों से अंततः बनता क्या है। जब उन्हें पहली बार चॉकलेट की एक बार (Bar) खिलाई गई, तो उनका रिएक्शन था– यह तो बहुत स्वादिष्ट है, हमें लगा था कि गोरे लोग हमारे बीजों से शराब या कोई दवा बनाते हैं। गरीबी और वैश्विक व्यापार की विसंगति के कारण, जो चॉकलेट पश्चिमी देशों के सुपरमार्केट में कुछ रुपयों या डॉलर्स में मिल जाती है, वह उन मजदूरों की कई दिनों की कमाई के बराबर होती है।

चॉकलेट का सफर आज से लगभग 3,500 से 4,000 साल पहले मध्य अमेरिका (मेसोअमरीका) में शुरू हुआ था। माया और एज़्टेक सभ्यताओं ने सबसे पहले कोको के पौधों को खोजा था। इसे देवताओं के भोजन की मान्यता थी, माया सभ्यता में कोको को पवित्र माना जाता था। वे इसे 'एक्सोकोलॉटल' कहते थे, जिसका अर्थ था 'कड़वा पानी'। वे आज की तरह मीठी चॉकलेट नहीं खाते थे, बल्कि कोको के बीजों को पीसकर उसमें पानी, सूखी मिर्च, वैनिला और मक्के का आटा मिलाकर एक झागदार, कड़वा और तीखा पेय बनाते थे। एज़्टेक साम्राज्य में कोको के बीज इतने कीमती थे कि उनका इस्तेमाल पैसों की तरह होता था। उदाहरण के लिए, उस दौर में 10 बीजों में एक खरगोश और 100 बीजों में एक अच्छा गुलाम खरीदा जा सकता था।

सोलहवीं शताब्दी में जब स्पेनिश खोजकर्ता हर्नान कोर्टेस ने मेसोअमरीका पर फतह हासिल की, तो उसने इस शाही पेय का स्वाद चखा। वह कोको के बीजों को अपने साथ स्पेन ले गया। यूरोपियनों को इसका कड़वा स्वाद पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसमें से मिर्च को हटाकर चीनी, शहद और दालचीनी मिला दी। देखते ही देखते यह नया मीठा पेय यूरोप के राजा-महाराजाओं और रईसों का स्टेटस सिंबल बन गया। यह इतना गुप्त और कीमती था कि स्पेन ने करीब 100 साल तक इस रेसिपी को पूरी दुनिया से छिपाकर रखा। उन्नीसवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने चॉकलेट को पीने वाले पेय से खाने वाली ठोस चॉकलेट (सॉलिड बार) में बदल दिया। इस बदलाव के पीछे बड़ी खोजें थीं। चॉकलेट बनाने की मशीन (कोचिंग मशीन) (Conching machine) का आविष्कार 'रोडोल्फ लिंड्ट' (Rodolphe Lindt) ने किया था। यह मशीन चॉकलेट को कई दिनों तक लगातार मथती है, जिससे उसकी कड़वाहट दूर होती है और वह मखमली रेशम जैसी चिकनी बनती है।

चॉकलेट की कहानी प्राचीन जंगलों से आधुनिक फैक्ट्रियों तक की अद्भुत यात्रा है। कभी देवताओं का पेय मानी जाने वाली यह वस्तु आज बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की पसंद बन चुकी है। स्वाद, विज्ञान, इतिहास और संस्कृति – इन सबका अनोखा संगम ही चॉकलेट को इतना विशेष बनाता है। चॉकलेट आज दुनिया भर में खुशियों, त्योहारों और प्यार का प्रतीक है। हर साल इसका वैश्विक बाजार अरबों डॉलर का कारोबार करता है। लेकिन इसके पीछे आइवरी कोस्ट और घाना जैसे देशों के लाखों गरीब किसान और बाल मजदूर हैं, जिन्हें आज भी ग्लोबल ट्रेड की विसंगतियों के कारण इस 'देवताओं के भोजन' का स्वाद नसीब नहीं होता। यही इस मीठी चॉकलेट की सबसे कड़वी दास्तान है।

सरोकार

डॉ.रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, भारत सरकार

किन्नरों के बजट को खर्च करने में कंजूसी क्यों?

हाल में संपन्न हुए संसद सत्र में इसी मुद्दे को सांसद संजय सिंह से राज्यसभा में पुरजोर से उठाकर व्यवस्था तंत्र का ध्यानाकर्षण करवाया। तभी, केंद्र सरकार ने नए सिरे से समीक्षा करने का मन भी बनाया है। समाज के दूसरे पारंपरिक समुदायों के मुकाबले ट्रांसजेंडर भी तरक्की करें, देश के विकास की मुख्यधारा में लोगों के साथ कदमताल मिलाएं, को ध्यान में रखकर ही इनके कल्याण के लिए तमाम सारी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। प्रत्येक वर्ष करोड़ों का बजट आवंटन होना आरंभ हुआ। लेकिन, दुर्भाग्य किसी भी साल पूरी धनराशि किन्नर कल्याण पर खर्च नहीं हुई। पैसा खर्च नहीं होना, निश्चित रूप से बड़ा मजाक ही कहा जाएगा।

ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन को बदलने वाली सरकारी योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाईं। केंद्र सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान बजट के रूप में आवंटित भारी-भरकम धनराशि प्रशासनिक लापरवाहियों के चलते खर्च ही नहीं हो सकी? प्रत्येक वर्ष का पैसा वापस जाता रहा। जबकि, किन्नरों को भी मुख्यधारा से जोड़ने को केंद्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रयास हुए थे। अगर ईमानदारी से पूरा पैसा खर्च किया जाता, तो किन्नर समुदाय में भारी बदलाव आया होता। सरकार-समाज ये दोनों वर्ग अच्छे से परिचित हैं कि किन्नरों को हमेशा से सामाजिक स्वीकार्यता से दूर रखा गया है। ट्रांसजेंडरों की संख्या भारत में लगभग 6 लाख के आसपास है। पिछली जनगणना में 4,87,803 संख्या सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है वहां 1,37,465 किन्नर रहते हैं। पर, अफसोस विकसित होते समाज में भी ये समूची आबादी अब भी हाशिए पर है।

हाल में संपन्न हुए संसद सत्र में इसी मुद्दे को सांसद संजय सिंह से राज्यसभा में पुरजोर से उठाकर व्यवस्था तंत्र का ध्यानाकर्षण करवाया। तभी, केंद्र सरकार ने नए सिरे से समीक्षा करने का मन भी बनाया है। समाज के दूसरे पारंपरिक समुदायों के मुकाबले ट्रांसजेंडर भी तरक्की करें, देश के विकास की मुख्यधारा में लोगों के साथ कदमताल मिलाएं, को ध्यान में रखकर ही इनके कल्याण के लिए तमाम सारी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। प्रत्येक वर्ष करोड़ों का बजट आवंटन होना आरंभ हुआ। लेकिन, दुर्भाग्य किसी भी साल पूरी धनराशि किन्नर कल्याण पर खर्च नहीं हुई। पैसा खर्च नहीं होना, निश्चित रूप से बड़ा मजाक ही कहा जाएगा।

पिछले 4-5 वर्षों में आवंटित धनराशि पर गौर करें, तो महसूस होगा कि वास्तव में कितना बड़ा विश्वासधात किन्नरों के साथ किया गया? कोविड-19 के बाद साल 2021-22 के केंद्रीय बजट में ट्रांसजेंडरों के लिए केंद्रीय बजट में 20 करोड़ रूपए आवंटित किए गए, जिसमें मात्र एक करोड़ 91 लाख ही खर्च हुए। यानी केवल 9.55 फीसदी धन खर्च हुआ। बाकी पैसा फिर से वापस चला गया। 2022-23 में इस धनराशि में इजाफा किया गया। 20 के जगह 30 करोड़ आवंटित हुए। लेकिन उसे भी खर्च नहीं किया गया। मात्र 12 लाख खर्च किए। संपूर्ण धनराशि का केवल आधा ही फीसदी? उसके बाद साल 2023-24 में और बढ़ोतरी करके 52 करोड़ 91 लाख रूपए किन्नर कल्याण कोष को दिए। दुर्भाग्य वह पैसा भी खर्च नहीं हुआ? सिर्फ 6 करोड़ 59 लाख खर्च हुए। यानी 12.45 फीसदी। 2024-25 में 68 करोड़ 46 लाख रूपए आवंटित किए, जिनमें भी केवल 5 करोड़ 14 लाख रूपए ही खर्च हुए। सिर्फ 7.5 फीसदी ही विभाग खर्च कर पाया। ये मजाक नहीं तो और क्या है?

किन्नर कल्याण योजना क्यों फिसड्डी साबित हुई? जवाबदेही किसकी है? ये बहस का बड़ा मुद्दा हो सकता था, लेकिन सामाजिक विमर्श से बाहर है। इसे प्रशासनिक सुस्ती कहें या सामाजिक बहिष्कार? कभी ऐसा प्रतीत होता है कि किन्नर-विकलांग जैसे लोगों के लिए योजनाएं जमीनी हकीकत को समझे बिना बनाई जाती हैं। ऐसे आयोगों में प्रमुख भी उन्हीं के बीचे से होने चाहिए जिससे लक्षित लाभार्थियों तक योजना पहुंच सके। आवंटित धनराशि का खर्च न होना और अपेक्षित परिणाम नहीं निकलने के पीछे क्या किन्नरों की सही से पहचान न होना तो मुख्य बाधाएं नहीं हैं? ऐसा है तो उसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां किन्नरों की आबादी बहुतायत संख्या में है जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार प्रमुख हैं। इन पांच राज्यों में करीब 3 लाख 80 हजार किन्नर हैं। किन्नर समुदाय सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक खुद को तीसरी श्रेणी में रखने की मांग लंबे समय से करते आए थे। मांग मानी भी गई। उसके बाद योजना आयोग ने 'यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया' की परियोजना में किन्नरों को अलग श्रेणी में रखने की अनुशंसा की। वर्ष 2010 में गृह मंत्रालय ने किन्नरों को पुरुष और महिला के अतिरिक्त तीसरी श्रेणी में रखने की मंजूरी दी। तब उम्मीद जगी कि अब किन्नरों को मुख्यधारा से जोड़ दिया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में किन्नरों को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का अवतार माना है, जहां उन्हें ना पूर्ण पुरुष और न ही पूर्ण स्त्री समझा गया है। इसलिए उन्हें शिव और शक्ति का संयुक्त रूप माना गया है। दरअसल, इस समय किन्नरों में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में इनमें शैक्षणिक स्कोर 37 फीसदी तक बढ़ा है। पढ़-लिखकर किन्नर विभिन्न किस्म के रोजगार में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। अब ये भीख मांगना नहीं चाहते, दुआओं-दुत्कारों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इनके भीतर अब इज्जत भरा जीवन जीने की ख्वाहिशें हैं।

सदियों से किन्नर सर्वाधिक अनक्षर रहे हैं। सरकारी योजनाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ भी? योजनाओं का लाभ पाने को लेकर हमेशा दस्तावेजीकरण संबंधित जटिलताएं आईं। जैसे, सिविल सर्जन से किन्नर होने का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज इनके आसानी से नहीं बन पाते। सामाजिक रूढ़िवादिता और भेदभाव के चलते किन्नर अक्सर योजनाओं के लिए आवेदन करने से भी कतराते हैं। यही कारण है कि अधिकांश किन्नर अब भी पारंपरिक रूप से बधाई मांगना, नाच-गाना या भिक्षावृत्ति से ही जुड़े हैं, जो उन्हें मुख्यधारा की रोजगार योजनाओं से दूर रखते हैं। केंद्र सरकार ने किन्नरों की विभिन्न मांगों को सुनकर ही सालाना बजट में इनकी हिस्सेदारी को भी सुनिश्चित किया है। योजनाएं फिसड्डी साबित न हों, इसके लिए दोबारा से प्रयास और समीक्षा करने की जरूरत है।

व्यंग्य

मुकेश नेमा
लेखक एमपी के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

लीकेज तस्दीक है कि सिस्टम कम कर रहा है

नी ट परीक्षा पेपर लीकेज को लेकर इतना भी रोना पीटना ठीक नहीं। लीकेज इस बात की तस्दीक है कि एक्जाम लेने वाला सिस्टम कायदे से,इसी दुनिया के हिसाब से ही चल रहा है। इंसान ही इसे चला रहे हैं। लीकेज ना मिलते इसमें तो वह ज्यादा परेशानी की बात होती। लीकेज हमेशा से हैं,हमेशा रहेंगे, इनका होना बुरा मानने जैसा नही है,इनके होने की खबर सरेआम हो जाना बुरा है।

लीकेज हैं,यानी छेद हैं। छेद अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवनोपयोगी चीज। सोचिए शरीर में उपलब्ध तमाम छेदों मे से कोई छिद्र असहयोग करने पर उतारू हो जाए तो आप क्या करेंगे ? छेद किसी भी सिस्टम को चलाने के लिये बेहद जरूरी चीज हैं। छेद ही वो प्रेरक तत्व है जिनकी वजह से इसे चलाने वाले लोग इसकी जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हैं। इन छेदों से लीक होता है अमृत। इसी अमृतपान की इच्छा से इसे चलाने वाले अपना कीमती वक्त देते है इसे। इसमें छेद ना हों,छेद ना करने दिये जाएं,तो ये कार सेवा करेगा कौन? हमारा सिस्टम अनाथ हो जायेगा और आप और हम मारे-मारे फिरेंगे।

भगवान की दया से अब तक ऐसा कोई भी सिस्टम ईजाद नहीं किया जा सका है जो लीक प्रूफ हो। ये छेद ही हैं जिनकी वजह से सिस्टम साँस लेता है। सिस्टम इन्हीं के भरोसे जीता है। छेद होते तो हैं सिस्टम में,पर इसे चलाने वाले इन्हें दिखाये जाने से परहेज करते हैं। सात परदों से ढक कर रखा जाता है छेदों को,पर कभी-कभी कुछ उत्साही,अधीर जन कुछ बडे ही छेद कर बैठते है इसमें। बड़ा छेद यानी बड़ा लीकेज। जब भी होता है ऐसा पब्लिक थोड़ी बहुत देर के लिये बुरा मान जाती है। सिस्टम छेद तो चाहता है पर छलनी मे बदल जाना उसे नागवार गुजरता है। ऐसे में छेदों की इज्जत बचाने के लिये ऐसे छेदीलाल निकाल बाहर किये जाते हैं या उन्हें दूर देश की रवानगी डालने के लिये वक्त और रास्ता दे दिया जाता है।

लीकेज क़तई बुरे भी नहीं होते। बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद लीक करने लगता है। लीक होते बच्चे को देखकर मम्मियाँ निहाल हो जाती हैं। थोड़ी सी बारिश मे गरीब का छप्पर लीक कर जाता है तो वह खुश होकर अपने सर पर छप्पर होने के लिये भगवान का शुक्रिया अदा करता है। लीकेजों को लेकर रोना पीटना बेकार है। लीकेज कहाँ नही हैं ? हमारे घरों तक पानी पहुँचाने वाले पाइप लाईन मे बरसो से लीकेज है।लाखों लीटर पानी बह चुका अब तक। करोड़ों और बहेगा। बालक वृद्ध सभी हिलमिलकर इससे बने तालाब मे छप छप करते है और खुश होते हैं।

सर पर आसमान है। आसमान ही फटा पड़ा है। आपकी जान बचाने वाली ओजोन लेयर में ही छेद है। इस छेद को भरने के लिये लाखो करोड़ों की योजनाएं है। इन योजनाओं में भी छेद है। छेद हैं तो लीकेज हैं। और लीकेज है तो सिस्टम जिंदा है और सिस्टम जिंदा है तो हम सभी अब तक जिंदा हैं।

लीकेज फायदेमंद न होते तो होते ही क्यों ? लीकेज होने की गुंजाइश उम्मीद जगाने जैसी है। लीकेज हैं इससे हर आदमी को लगता है कि वो भी कुछ बन सकता है। लीकेज ढूँढना और उसमें घुस पड़ना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यदि ये लीकेज कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होती। गोपनीयता भंग न होती इसकी तो अच्छा होता। कुछेक सैकड़ा समर्थ बच्चे एडवांस में पेपर पा जाते। दूसरों की जगह डॉक्टर बन जाते। ये बनते तो झोला छाप नीम हकीमों से थोड़े से बेहतर ही होते,उनसे कम मरीज मारते। याद रखिए घोड़ों के होते हुए भी गधों की कभी बेइज़्ज़ती नही की जाती। लीकेज की खबर लीक न होती तो कुछ काबिल मेहनती बच्चे भी डॉक्टर बन सकते थे। लीकेज की इस खबर से शातिर और होनहार सभी तरह के बच्चों का साल बिगड़ा है। डॉक्टरों का भीषण टोटा है हमारे यहाँ। ऐसे में लीकेज की इस खबर के सार्वजनिक होने से देश का नुकसान ही हुआ है। हम कुछ काबिल और थोड़े से नालायक डॉक्टरों से वंचित रह गए है।

कहने का सार यह कि कुल मिलाकर छेद और छेदो मे से होने वाले लीकेज बुरे नहीं है। उनके होने की खबर जगज़ाहिर होना बुरा है। और जिसने भी इनके होने की खबर लीक की है उसे अवाम को कभी भी दिल से माफ नही करना चाहिए।

कलेक्टर डॉ.सोनवणे ने समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश

शत-प्रतिशत राजस्व लक्ष्य की पूर्ति करें अधिकारी : कलेक्टर

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गुरुवार को आयोजित बैठक में आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, खनिज विभाग, जिला उप पंजीयक और वाणीज्य कर विभाग की समीक्षा कर निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्धारित राजस्व लक्ष्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली कार्यों में तेजी लाई जाए और अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए। आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि ओवररेटिंग की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानों के विरुद्ध तत्काल प्रकरण दर्ज कर पेनाल्टी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने अवैध रूप से शराब बिक्री के विरुद्ध राजस्व एवं आबकारी के अमले को संयुक्त निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही नियमित मॉनिटरिंग कर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

चेक पोस्ट कर्मचारियों को ड्रेस-आई कार्ड अनिवार्य

कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बैठक में आरटीओ को निर्देश दिए कि चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से निर्धारित ड्रेस एवं आई कार्ड पहनकर ही ड्यूटी करें। उन्होंने कहा कि कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत की जाए। कलेक्टर ने ओवरलोड वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया जाए। इसके अलावा उन्होंने खनिज विभाग, जिला उप पंजीयक कार्यालय और वाणीज्य कर विभाग को प्राप्त राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।

पवार समाज ने किया जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के कर्मचारियों का सम्मान

बैतूल। पवार समाज वरिष्ठ जन कल्याण मंच, बैतूल द्वारा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बैतूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पवार समाज के अध्यक्ष एवं मानद कैप्टन एलआर पवार (से.नि.) के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्र सेवा तथा सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे समस्त शासकीय सेवकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते पवार समाज के अध्यक्ष कैप्टन एल.आर. पवार (से.नि.) ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित करने का अवसर हमें मिला।

उन्होंने कहा कि कार्यालय का समस्त स्टाफ पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं आश्रितों के पेंशन, छात्रवृत्ति तथा केंद्र व राज्य की योजनाओं से संबंधित कार्यों हेतु निष्ठा भाव एवं ईमानदारी से कार्य करता है। कार्यक्रम के दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन (नौसेना) सुमीत सिंह (से.नि.) ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे सेवाकाल में यह पहला अवसर है, जब किसी सामाजिक संगठन द्वारा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के सभी शासकीय सेवकों को एकसाथ सम्मानित किया जा रहा है। पवार समाज की यह पहल सराहनीय एवं सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर से.नि. कैप्टन सुमीत सिंह जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, से.नि. नायब सूबेदार अमित भूमरकर असिस्टेंट ग्रेड-2, से.नि. कार्यालय अधीक्षक सूबेदार आर.एस. सोलंकी, से.नि. कल्याण संयोजक सूबेदार जगदीश साहू, समिति सुपरवाइजर, से.नि. हवलदार अर्जुन बिसन्द्रे, असिस्टेंट ग्रेड-3, से.नि. हवलदार सुरेंद्र कुमार डोंगरे, असिस्टेंट ग्रेड-3, मुस्कान सरोने समिति लिपिक, से.नि. नायक लील सिंह, भृत्य और अविनाश इन्हे केयर टेकर को सम्मान चिन्ह एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पवार समाज के वरिष्ठ सदस्य एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 'संपर्क अभियान 2026' को मिली बड़ी सफलता

772 शिविरों में 34 हजार 702 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर निराकरण

भोपाल। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को उनके घर के नजदीक ही निराकरण करने के उद्देश्य से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित 'संपर्क अभियान 2026' को सफलता मिली है। 14 मई से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत भोपाल और ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में व्यापक स्तर पर 772 विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 34 हजार 702 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया।

भोपाल रीजन के वृत्तों में लगे शिविर- भोपाल रीजन के अंतर्गत सबसे अधिक 69 शिविर शहर वृत्त भोपाल में आयोजित किए गए जिसमें 4,606 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया, इसके साथ ही बैतुल वृत्त में 63 शिविरों में 2,802 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, सीहोर वृत्त में 51 शिविरों में 1,039 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, राजगढ़ वृत्त में 48 शिविरों में 500 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, नर्मदापुरम वृत्त में 47 शिविरों में 5,586 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, रायसेन वृत्त में 38 शिविरों में 2,421 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, भोपाल (ग्रामीण) वृत्त में 37 शिविरों में 1,489 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, विदिशा वृत्त में 24 शिविरों में 1,541 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण एवं हरदा वृत्त में 20 शिविरों में 4,271 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया है।

ग्वालियर रीजन के वृत्तों में लगे शिविर- ग्वालियर रीजन के अंतर्गत मुरैना वृत्त में 59 शिविरों में 1,438 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, शहर वृत्त ग्वालियर में 44 शिविरों में 1603 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, भिंड वृत्त में 44 शिविरों में 809 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, गुना वृत्त में 38 शिविरों में 932 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, ग्वालियर (ग्रामीण) वृत्त में 39 शिविरों में 612 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, श्योपुर वृत्त में 30 शिविरों में 1,228 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, दतिया वृत्त में 26 शिविरों में 1,288 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, शिवपुरी वृत्त में 73 शिविरों में 1,344 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण एवं अशोकनगर वृत्त में 22 शिविरों में 1,193 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया।

इन शिकायतों और सेवाओं पर हुआ त्वरित काम- इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान करना है। शिविरों में मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण बिल, मीटर रीडिंग और अन्य बिलिंग संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही मात्र 5 रुपये में नवीन ग्रामीण घरेलू एवं कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान किये गए। वहीं भार वृद्धि, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, स्थाई कनेक्शन विच्छेदन, अस्थायी कनेक्शन, ई-केवायसी और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC), बंद/खराब मीटर बदलना, स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतें, सर्विस केबल सुधार, वोल्टेज की समस्या और ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतों, बिजली बिलों का आंशिक एवं पूर्ण भुगतान, अग्रिम भुगतान पर छूट, बकाया राशि भुगतान तथा अन्य जनहितैषी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किया गया ।

सफलता की कहानियां

सुखरास के नितिन गुर्जर का बिजली बिल सुधरा (हरदा)

संपर्क अभियान के तहत आयोजित संपर्क शिविर बिजली उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक सफलता का मामला हरदा वृत्त के हरदा उत्तर संभाग अंतर्गत हरदा दक्षिण वितरण केंद्र का है, जहाँ एक किसान के बिजली बिल की शिकायत का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में ग्राम सुखरास निवासी आवेदक श्री नितिन पिता गवू प्रसाद गुर्जर ने अपनी समस्या दर्ज कराई थी। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उनके घर पर बिजली का स्वीकृत लोड (भार) बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद मासिक बिजली बिल काफी अधिक आ रहा है, जिससे वे परेशान थे। शिकायत मिलते ही विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए त्वरित कार्रवाई की। वितरण केंद्र की टीम द्वारा तुरंत उपभोक्ता नितिन गुर्जर के परिसर का भौतिक सत्यापन कर लोड (भार) चेक कराया गया। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई और परिसर का वास्तविक भार कम मिला।

कंप्यूटर क्रांति और सूचना तकनीक के जनक थे राजीव गांधी : निलय डागा

पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय में जुटे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता

बैतूल। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार 21 मई को जिला कांग्रेस कार्यालय बैतूल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देश के प्रति उनके योगदान और आधुनिक भारत निर्माण में निभाई गई भूमिका को याद किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा ने कहा कि राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर क्रांति और सूचना तकनीक के जनक थे। उन्होंने देश को आधुनिक तकनीक से जोडने का कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप आज भारत विश्व स्तर पर सूचना तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने युवाओं को नई सोच और नई दिशा देने का काम किया तथा देश में दूरसंचार व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री डागा ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त कर गांवों तक लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित की। उनके कार्यकाल में शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका लाभ आज भी देश को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का सपना आधुनिक, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का था, जिसे कांग्रेस आज भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

तय अवधि से पहले बैतूल जिले में पूर्ण हुआ मकान सूचीकरण कार्य

बैतूल। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य निर्धारित अवधि से पूर्व 19 मई 2026 को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के प्रभावी समन्वय कौशल, प्रेरक नेतृत्व एवं सतत मार्गदर्शन तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट की निरंतर मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई। जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी नरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि सभी चार्ज अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, प्रगणकों एवं तकनीकी दल के समन्वित प्रयासों, अथक परिश्रम से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यापक कार्य तकनीकी एवं मैदानी चुनौतियों के बावजूद सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सतत मैदानी निरीक्षण, त्वरित समस्या समाधान एवं कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने से जिले ने निर्धारित समय-सीमा से पूर्व यह उपलब्धि हासिल की।

प्रगणकों की मेहनत और सतत मॉनिटरिंग से मिली सफलता- जिले के 21 चार्जों में लगभग 2800 गणना ब्लॉकों के लिए नियुक्त 2433 प्रगणकों एवं 411 पर्यवेक्षकों द्वारा घर-घर पहुंचकर मकानों की नंबरिंग, नजरी नक्शा तैयार करने एवं एचएलओ ऐप के माध्यम से डेटा प्रविष्टि का कार्य किया गया। फील्ड में कार्यरत टीमों ने भीषण गर्मी के बावजूद पूरी जिम्मेदारी और उत्साह के साथ कार्य संपादित किया। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी, जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, चार्ज अधिकारियों, जिला प्रभारी एवं मास्टर ट्रेनर्स द्वारा लगातार फील्ड भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता की जांच की गई तथा मौके पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिला जनगणना कार्यालय की तकनीकी टीम एवं मास्टर ट्रेनर, कंट्रोल रूम द्वारा एचएलओ ऐप से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया, जिससे कार्य प्रभावित नहीं हुआ।

भगवान् शिव, माता पार्वती विश्वास का प्रतीक हैं, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ, सत्संग से सभी का उद्धार : श्री मिश्र उड़ीसा

(हीरालाल गोलानी)

भोपाल। भगवान् शिव एवं माता पार्वती विश्वास का प्रतीक हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी भगवान् विष्णु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान् विष्णु को नहीं पा सकते। भगवान् भोलेनाथ शिव शंकर को राम नाम अत्यंत प्रिय है। निरंतर भगवंत जप श्रद्धा से करते रहने से भगवंत प्राप्ति भी दुर्लभ नहीं है। इस धरा पर काम,कर्म,अर्थ धर्म,मोक्ष गूढ़ रहस्य है। भगवान् विष्णु के प्रति श्रद्धा, विश्वास के प्रति समर्पण की भावना से प्रेरित होकर जप करता रहे। भगवान् हर मानव जाति एवं पशु पक्षियों, चींटियों अर्थात आत्मा स्वरूप सभी में विद्धमान हैं। प्रभु हमेशा निर्बल के साथ उनके रक्षक, रखवाला है भजन लिखने वाला भगवान् को अवश्य प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। फिर जन्म मिले न मिले इस कारण मानव मात्र को श्रीमद्भागवत पुराण कथा के सत्संग में मन

लगाना चाहिए।सत्संग में प्रत्येक देवी-देवताओं का आगमन होता है। यह साथ समस्त धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है।श्रीमद्भागवत कथा सत्संगऐसी संजीवनी बूटी है। जिसके श्रवण मात्र समस्त मानव प्राणी ही नहीं, पशु पक्षियों, वृक्षों, चांडाल आदि का भी उद्धार हो जाता है। इसके लिए श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। ऐसी लगन लगाओ कि फिर जन्म न मिले। उक्त उद्गार जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान पंडित डॉ काशीनाथ मिश्र उड़ीसा ने भोपाल गर्ल्स स्कूल पंचवटी परिसर में श्रीमती नीरजा गोलानी खूबचदानी एवं पंकज खूबचदानी द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा एवं भविष्य मालिका पुराण की कथा के अवसर पर कहें।इसी अवसर प्रमुख ब्रह्माकुमारी दीदियों ने उड़ीसा में भविष्य मालिका पुराण प्रथम खंड के रचयिता डाक्टर काशीनाथ मिश्र का स्वागत किया। वहीं ब्रह्माकुमारी दीदियों ने श्री मिश्र को श्रीकृष्ण का चित्र भेंट किया। श्री मिश्र जी ने भी दीदियों को भविष्य मालिका पुराण की प्रति प्रदान करते शाल से स्वागत किया। इसी क्रम में नव नियुक्त जिला भाजपा महामंत्री भोपाल चेतन जी भार्गव ने भी श्री मिश्र जी का स्वागत किया।आपने कथा को विस्तार देते हुए कहा कि वर्तमान में कथाओं का व्यवसायीकरण हो गया है। यह चिंताजनक स्थिति है। आपने कहा कि सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि सभी जीवों का उद्धार हो जाता है।इसका सभी को सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए। आपने कई उदाहरण देकर कहा मुक्ति कैसे मिली किन किन विख्यात को मिली बताया। आपने आगे कहा कि यह जीवन नश्वर है।बाद में पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। वर्तमान जीवन में सत्य वचन बोलें माधव, गोविंद, गोपाल भजे।

संक्षिप्त समाचार

नशामुक्त भारत अभियान के तहत द्वितीय दिवस प्रशिक्षण दिया

रायसेन (निप्र)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग संचालनालय भोपाल तथा मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में रायसेन जिला मुख्यालय स्थित डाइट सभागृह में नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत चार दिवसीय जिला स्तरीय मास्टर वालंटियर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। जिसके द्वितीय दिवस बुधवार को जिले के विकासखंड बेगमगंज, सिलवानी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर वालंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता फैलाना है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले वालंटियर अब अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देंगे और उन्हें नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान श्रीमती सरिता प्रजापति संचालक जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी द्वारा नशे से दूरी बनाए रखने हेतु उपस्थित जनसमूह को शपथ दिलाई। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय रायसेन मनकक्ष में पदस्थ डॉक्टर कल्पेश द्वारा नशे से होने वाले मानसिक रोग व नशे दूरी बनाए रखने संबंधी उपाए बताए और किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता मिथुन यादव ने किशोर तथा युवाओ में बढ़ रहे नशे को ध्यान रखते हुए, उन्हें नशे से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण में उपसंचालक सामाजिक न्याय श्री मनोज बॉथम, मास्टर ट्रेनर श्री राजीव वेद, श्री प्रकाश शर्मा, उत्कर्ष नशा मुक्ति केंद्र वाल्मीकि की ओर से प्रशांत चौहान कोऑर्डिनेटर के रूप में उपस्थित रहे।

तीन माह से अधिक समयावधि का कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित ना रहे: कलेक्टर

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को राजस्व प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि तीन माह से अधिक समयावधि का कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित ना रहे। सभी एसडीएम से नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की संख्या, गत दिवस निराकृत किए गए प्रकरणों और आज निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों की जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को अनुभाग स्तर पर अन्य विभागों की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की मॉनिटरिंग करने और फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

गेहूँ उपार्जन में खरीदी पावती जारी न होने वाले किसानों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश

विदिशा (निप्र)। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के दौरान जिन किसानों से गेहूँ खरीदी के उपरांत खरीदी पावती जारी नहीं हुई है, उनकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि किसानों को तौल पर्ची जारी किया जाना अनिवार्य है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कई उपार्जन केन्द्रों द्वारा बिना तौल पर्ची जारी किए किसानों से गेहूँ खरीदा गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि तौल पर्ची जारी नहीं होने के कारण संबंधित किसानों के स्लॉट की वैधता आगे नहीं बढ़ाई जा पा रही है, जिससे किसानों को खरीदी पावती प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। ऐसे मामलों के निराकरण हेतु सभी उपार्जन केन्द्रों को निर्देशित किया गया है कि वे केन्द्रवार निर्धारित प्रारूप में उन किसानों की सूची तैयार करें, जिनकी स्लॉट वैधता समाप्त हो चुकी है तथा जिनसे केन्द्रों पर गेहूँ की तौल की जा चुकी है। उक्त जानकारी एक्सल शीट एवं हार्डकॉपी दोनों स्वरूपों में संबंधित कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भेजी जाएगी, ताकि किसानों के स्लॉट की अवधि बढ़ाने की कार्रवाई की जा सके तथा तौल के अनुसार खरीदी पावती ऑनलाइन जारी कराई जा सके।

किसान कल्याण वर्ष तहत पिपलधार में कृषि रथ के साथ वृहद कृषक संगोष्ठी आयोजित

वैज्ञानिक खेती, ई-टोकन व्यवस्था, डेयरी योजनाओं और नरवाई प्रबंधन पर किसानों को दी गई विस्तृत जानकारी

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में 'किसान कल्याण वर्ष 2026' के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे कृषि रथ अभियान को किसानों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में विकासखंड नटेरन के ग्राम पिपलधार में कृषि रथ कार्यक्रम अंतर्गत वृहद कृषक संगोष्ठी का सफल आयोजन आज किया गया था। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों, जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में किसानों की सहभागिता रही। कृषि रथ के माध्यम से गांव-गांव पहुंच रही आधुनिक खेती की जानकारी क्षेत्रीय कृषि अधिकारी सुश्री संगम रघुवंशी ने बताया कि जिले के प्रत्येक विकासखंड की चयनित ग्राम पंचायतों में कृषि रथ का नियमित भ्रमण कराया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं, तकनीकी सुधारों तथा आधुनिक खेती की पद्धतियों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कृषक संगोष्ठियों में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित अन्य विभागों की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य और फसल विविधीकरण पर दिया गया मार्गदर्शन आत्मा परियोजना के विकासखंड तकनीकी प्रबंधक श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा फसल विविधीकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, ई-विकास प्रणाली अंतर्गत ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था तथा पराली प्रबंधन के बारे में भी किसानों को जागरूक किया। साथ ही खेती को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि वैज्ञानिक ने बताए लाभकारी खेती के तरीके कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से आए कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजमोहन शर्मा ने कृषकों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, नरवाई प्रबंधन तथा वैज्ञानिक खेती के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसानों को बताया कि आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। डॉ. शर्मा ने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने पर उत्पादन लागत कम होती है और आय में वृद्धि संभव होती है। इमलिया जागीर और बींझ में भी हुआ किसानों से संवाद कृषि रथ ग्राम पंचायत इमलिया जागीर पहुंचा, जहां कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने किसानों को नई ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था और विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। किसानों ने मूल्य संवर्द्धन एवं कृषि आधारित योजनाओं में गहरी रुचि दिखाई और अधिकारियों से योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके बाद कृषि रथ ग्राम पंचायत बींझ पहुंचा, जहां किसानों ने शासन की कृषि योजनाओं से प्राप्त लाभों के अनुभव साझा किए।

डेयरी, बकरी एवं कुक्कुट पालन योजनाओं की दी जानकारी

ग्राम पिपलधार में आयोजित संगोष्ठी में कृषि विस्तार अधिकारी श्री अभिषेक जैन ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने आचार्य विद्यासागर दुग्ध गौ संवर्धन योजना, डेयरी प्लस योजना तथा बकरी एवं कुक्कुट पालन योजनाओं के संबंध में किसानों को विस्तार से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि कृषि के साथ पशुपालन को जोड़कर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। नरवाई नहीं जलाने की दिलाई गई शपथ कृषक संगोष्ठी के दौरान ग्राम पंचायत पिपलधार में बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों एवं ग्रामीणों को नरवाई प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। सरपंच श्री रामराज सिंह यादव ने किसानों से नरवाई नहीं जलाने की अपील करते हुए पर्यावरण संरक्षण और भूमि की उर्वरता बनाए रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर सभी किसानों को नरवाई न जलाने की शपथ भी दिलाई गई। अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी रहे उपस्थित कार्यक्रम में कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी श्री सत्यम नेमा, श्री अभिषेक जैन, श्री अनिल बघेल, श्री लक्ष्मण सिंह गुर्जर, श्री विकास शाक्य, श्री रजत जैन, श्री राघवेंद्र अहिरवार, सुश्री शालिनी रघुवंशी, सुश्री तुलसा, सुश्री संगम रघुवंशी, आत्मा परियोजना से श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला प्रभारी श्री अरविंद यादव, फसल बीमा प्रतिनिधि श्री जितेंद्र यादव सहित पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

किसानों को उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी दे रहा कृषि रथ

बैतूल (निप्र)। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में बुधवार को आठनेर विकासखंड की ग्राम पंचायत कावला, सातकुंड एवं गोंडी घोघरा में कृषि रथ पहुंचा। इस दौरान कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई।

वहीं कृषि की नवीन तकनीक से खेती में लाभ, खेती के साथ-साथ अन्य गतिविधियों को भी सम्मिलित करने की सलाह दी गई। साथ ही शासन द्वारा संचालित ई-विकास प्रणाली के लाभ और ई टोकन प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। फॉर्मर आईडी में शेष खसरा नंबर को जोड़ने की सलाह के साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया। ताकि शुद्ध गुणवत्ता की उपज प्राप्त कर मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सके।

इस दौरान दलहन, तिलहन फसल के विस्तार व उत्पादन एवं विपणन की भी जानकारी दी गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत निःशुल्क मिट्टी नमूने की जांच और एसएचसी के अनुरूप उर्वरक उपयोग की जानकारी बताई गई। साथ ही नरवाई प्रबंधन और उसके लाभों की जानकारी प्रदान कर नरवाई न जलाने की अपील की गई। इस अवसर पर किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उचित उत्तर और सलाह दी गई।

मेरा युवा भारत द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग एवं पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रायसेन (निप्र)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार मेरा युवा भारत रायसेन द्वारा सांची विकासखंड अंतर्गत सांची पुलिस स्टेशन में 'सामुदायिक पुलिसिंग एवं पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली' विषय पर अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक 20.05.2026 को किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था के महत्व तथा समाज में पुलिस की भूमिका से अवगत कराना था।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस थाना के प्रमुख थाना प्रभारी श्री जेपी त्रिपाठी द्वारा प्रतिभागियों को थाना स्तर पर संचालित विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि कानून एवं व्यवस्था किसी भी समाज की शांति, सुरक्षा और विकास की आधारशिला है। पुलिस विभाग अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, आपातकालीन सहायता तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्य करता है। प्रतिभागियों को थाना परिसर का भ्रमण कराया गया तथा शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, साइबर अपराध से बचाव, आपातकालीन सेवाओं एवं जनसहयोग आधारित पुलिसिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सहायता एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर एक सहयोगी संस्था भी है। कार्यक्रम में सामुदायिक पुलिसिंग के महत्व पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान मेरा युवा भारत की डिप्टी डायरेक्ट श्रीमती मोनिका चौधरी एवं श्री जीतू ठाकुर समिति सदस्य माय भारत ने कहा कि पुलिस एवं आमजन के बीच बेहतर समन्वय से अपराधों की रोकथाम, सामाजिक सौहार्द एवं सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा मिलता है। युवाओं से अपील की गई कि वे जागरूक नागरिक बनकर सामुदायिक पुलिसिंग गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करें तथा समाज में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को निकट से समझने का अवसर मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा इसे युवाओं के लिए अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक पहल बताया।

स्थानीय निकाय निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण 2026 को लेकर सिवनीमालवा में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

नर्मदापुरम (निप्र)। स्थानीय निकाय निर्वाचक नामावली के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2026 के सुचारू संपादन को लेकर मंगलवार को सांदीपनि स्कूल सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नर्मदापुरम श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार आयोजित बैठक की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विजय राय ने की। बैठक में क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त स्टैंडिंग कमेटी सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्थानीय निकाय निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जनप्रतिनिधि अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकृत कर्मचारियों (बीएलओ) के माध्यम से मतदाता नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के लिए निर्धारित प्रारूप फॉर्म ईआर-1, ईआर-2 एवं ईआर-3 की उपयोगिता को समझें तथा आमजन को इसके प्रति जागरूक करें। बैठक में यह भी बताया गया कि कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित न रहे तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल न हों, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2026 के लिए जारी अधिकृत कार्यक्रम एवं समय-सीमा की जानकारी भी साझा की गई। अनुविभागीय अधिकारी श्री विजय राय ने सभी राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

फल अनुसंधान केंद्र का कृषि विकास समिति के सदस्यों ने किया भ्रमण

सीहोर (निप्र)। भोपाल के ईटखेड़ी में कृषि विकास समिति ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा संचालित फल अनुसंधान केंद्र का भ्रमण किया। भ्रमण में सदस्यों ने आम, नींबू और अमरूद की किस्में देखीं और उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी। इस दौरान सीहोर के आरएके कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा ग्राफ्टिंग, पौध संवर्धन एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। समिति के भ्रमण का उद्देश्य किसानों से प्रत्यक्ष संवाद करना था, ताकि धरातल पर मौजूद चुनौतियों और समस्याओं को जाना जा सके और उसे शासन की नीति और योजनाओं के माध्यम से दूर किया जा सके। समिति के सदस्यों ने किसानों से चर्चा भी की। इस दौरान किसानों को नरवाई नही जलाने के लिए भी प्रेरित किया गया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है पशुपालन

पशुपालन योजनाओं के माध्यम से बढाया जा सकता है स्थानीय स्तर पर रोजगार : कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने ग्राम शाहपुर कोड़िया एवं ग्राम बमुलिया में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत संचालित बकरी एवं पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पशुपालकों से चर्चा कर योजनाओं से मिल रहे लाभ, स्वरोजगार की संभावनाओं, पशुपालन की आधुनिक तकनीकों तथा गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने कहा कि शासन की पशुपालन आधारित योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जिससे उनकी आय में वृद्धि होने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने ग्राम शाहपुर कोड़िया में श्रीमती ममता राय द्वारा संचालित बकरी फॉर्म का निरीक्षण करते हुए वहां पाली जा रही विभिन्न नस्लों की बकरियों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि फॉर्म में सिरोही, बीटर सहित पांच प्रकार की नस्लों का पालन एवं संवर्धन किया जा रहा है। कलेक्टर ने बकरियों की देखरेख, उनके आहार, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, प्रजनन प्रक्रिया तथा पालन-पोषण की संपूर्ण व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यह भी जाना कि विभिन्न नस्लों की बकरियां किन क्षेत्रों से लाई जाती हैं तथा उनके पालन के लिए किस प्रकार की आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। फॉर्म संचालक ने कलेक्टर को बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर इस बकरी फॉर्म की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि बकरी पालन व्यवसाय से उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है तथा इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुपालकों को समय-समय पर प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे आधुनिक पद्धतियों का उपयोग कर अधिक लाभ अर्जित कर सकें। उन्होंने कहा कि पशुपालन केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

इसके पश्चात कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने ग्राम बमुलिया पहुंचकर श्री खलील खान द्वारा संचालित पोल्ट्री फॉर्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फार्म संचालक ने जानकारी दी कि उनके फार्म में कड़कनाथ, जापानी स्क्वेल एवं देशी नस्लों की मुर्गियों का पालन किया जा रहा है। कलेक्टर ने पोल्ट्री फॉर्म की व्यवस्थाओं, मुर्गियों की देखरेख, आहार प्रबंधन, स्वच्छता तथा अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े हितग्राहियों को आवश्यक तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि जिले में इस क्षेत्र का और अधिक विस्तार हो सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन सहित पशुपालन विभाग की सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि पशुपालन गतिविधियां कृषि के साथ जुड़कर किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आने वाले समय में यह क्षेत्र ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बनेगा।

रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहने का किया आग्रह

भोपाल। रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन, सीसीटीवी जैसे नवीनतम तकनीकी उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। रेलगाड़ियों, यात्रियों, स्टेशन परिसर और विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बीट स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आज नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में रेल मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में देश भर के फील्ड अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। रेल भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह

बिट्टू के अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी इस बैठक में उपस्थित थे। हाल ही में हुई आगजनी की कुछ घटनाओं सहित कई मामलों की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता सामने आई है। भारतीय रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) इनकी सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। कई मामलों में, रेलवे की त्वरित और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। खुफिया प्रणालियों को मजबूत करने और सूचनाओं को तेजी से संसाधित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा, रेलवे मंत्रालय यात्रियों को यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में प्रतीक्षा करते समय असामाजिक गतिविधियों को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया है। रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना देने को कहा गया है।

सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान हुई चर्चाओं में, बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से जमीनी स्तर से खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने, रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा फील्ड जोन के बीच परिचालन सुरक्षा तालमेल को सुधारने पर भी बल दिया गया। बैठक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, कैमरों की विशिष्टताओं को उन्नत करने और एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों को तैनात करने पर भी विचार किया गया। बैठक में रेलवे नेटवर्क में अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन के लिए आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के बीच सूचना साझाकरण तंत्र को बेहतर बनाकर आपसी तालमेल को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

7:20 पर जिंदा ऊपर गई, 8:20 पर नीचे आई लाश

एफआईआर में मौत का वक्त 10:50, हैरान कर रही कहानी

भोपाल। पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब पूरी तरह से एक उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका है। बुधवार को भोपाल की एक अदालत में सुनवाई के दौरान मृतका के वकील ने पुलिस तफ्तीश और एम्स की पोस्टमार्टम प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। कोर्ट में वो सवाल उठाए गए, जिन्होंने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या 12 मई की रात को छत पर जो हुआ, क्या उसे दबाने की कोशिश की जा रही है।

सीसीटीवी ने उड़ाई पुलिस की नींद

केस में सबसे बड़ा और सनसनीखेज मोड़ सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग से आया है। कोर्ट में दी गई दलील के मुताबिक, 12 मई की शाम 7:20 बजे ट्विशा को जिंदा सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ जाते देखा गया। इसके ठीक एक घंटे बाद, यानी रात 8:20 बजे तीन लोग ट्विशा की लाश को नीचे लाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन, हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की एफआईआर में ट्विशा की मौत का समय रात 10:50 बजे दर्ज है। हालांकि जानकारों का कहना है कि सीसीटीवी का टाइमस्टैम्प कभी-कभी गलत जानकारी दे देता है।

पोस्टमार्टम से गायब थी बेल्ट, हाइट भी बदली- ट्विशा के वकील ने एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी गंभीर उंगलियां उठाई हैं। कोर्ट को बताया गया कि जिस बेल्ट से फंदा लगाने का दावा किया जा रहा है, उसे समय पर अस्पताल भेजा ही नहीं गया। ऐसे में डॉक्टरों ने गले के निशानों का मिलान कैसे किया? यही नहीं, पुलिस की केस डायरी और एम्स की पीएम रिपोर्ट में ट्विशा की लंबाई में भी अंतर पाया गया है। इसके अलावा, एफआईआर में ट्विशा की उम्र एक जगह 1987 के हिसाब से लिखी है, तो दूसरी जगह 33 और 31 साल दर्ज है। परिवार का आरोप है कि ये मामूली लिपिकीय त्रुटियां नहीं, बल्कि रसूख के दबाव में की गई गड़बड़ियां हैं। अदालत में मृतका के वकील ने तीखा सवाल किया कि पोस्टमार्टम के दौरान एम्स में ट्विशा की सास (पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह) की बहन क्यों मौजूद थीं, जो एक निजी अस्पताल में काम करती हैं? साथ ही, मौत के तुरंत बाद लोकल थाने को सूचना क्यों नहीं दी गई? फिलहाल, इस मामले में एक बड़ा घटनाक्रम यह रहा कि पुलिस ने कोर्ट में लिखित तौर पर दे दिया है कि उन्हें दोबारा पोस्टमार्टम कराने पर कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी तरफ, पुलिस ने कागजों में लिख दिया कि शव परिवार को सौंप दिया गया है, जबकि ट्विशा की बॉडी 13 मई से मर्चुरी में रखी हुई है और परिवार ने इंसाफ मिलने तक इसे लेने से मना कर दिया है।

संपत्ति का डिजिटल डेटाबेस बनाने की योजना, ताकि राजस्व आए

मप्र की अरबों की संपत्ति 'गुमशुदा, दिल्ली से रामेश्वरम् तक फैली प्रॉपर्टी का हिसाब नहीं

भोपाल। देश के दूसरे राज्यों में मप्र की अरबों रुपयों की संपत्तियां हैं, लेकिन इनकी मौजूदा स्थिति की पक्की जानकारी सरकार के पास नहीं है। अब मप्र सरकार इन बिखरी संपत्तियों का वैल्युएशन और लीगल स्टेटस का डेटाबेस तैयार कराने जा रही है, ताकि जरूरत के हिसाब से इनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा सके। राज्य के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अधीन लोक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (पीएएमसी) को यह काम सौंपा है। ऐसे 4 विभाग हैं, जिनके पास प्रदेश के बाहर अचल संपत्तियां हैं। सर्वाधिक संपत्तियां धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के पास हैं। कंपनी ने चारों विभागों से उनकी संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। तीन माह से चल रहे पत्राचार के बाद तीन विभागों ने तो ब्योरा दे दिया लेकिन धर्मस्व विभाग ने अब तक जानकारी नहीं दी है। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी कहते हैं, राज्य के बाहर मप्र की संपत्तियों का डेटाबेस तैयार करने हमने सभी विभागों से जानकारी मांगी थी, धर्मस्व विभाग की ओर से अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। बाकी अन्य विभागों से मिली जानकारी के आधार पर काम किया जा रहा है।

पीएएमसी को जिम्मा- विवादों को हल करें- कई संपत्तियों के पुराने रिकॉर्ड तो मौजूद हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन से स्पष्ट हो सकेगा कि कोई कब्जा या अतिक्रमण तो नहीं है। ऐसी संपत्तियां जिनका विधिवत कानूनी रिकार्ड नहीं है।

लोक निर्माण विभाग

कोठी परान, झांसी- यहां सिंधिया स्टेट की 19 एकड़ में फैली कोठी परान को मध्यभारत राज्य को सौंपा गया था। मध्यभारत का विलय होने के बाद संपत्ति मप्र को मिली। अभी उप्र का कब्जा।

नई दिल्ली- चाणक्यपुरी में रोज एंड मेरी मार्ग पर स्थित मध्यप्रदेश भवन और बसंत कुंज स्थित मध्यांचल भवन है। दोनों मप्र सरकार के गेस्टहाउस के रूप में इस्तेमाल होते हैं।

मुंबई- वाशी और चर्चगेट के पास स्थित राज्य सरकार के गेस्ट हाउस और कार्यालय हैं। इनको लेकर कोई विवाद नहीं हैं।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की ये संपत्तियां, लेकिन इनकी सटीक जानकारी नहीं- वाराणसी (काशी)- घाटों के पास स्थित धर्मशालाएं और मंदिर। इनका उपयोग मप्र के तीर्थयात्री करते रहे हैं। प्रयागराज (इलाहाबाद) - कुंभ क्षेत्र और संगम के पास इस विभाग की जमीन और पुराने आश्रम मौजूद हैं। मथुरा-वृंदावन - दोनों ही शहरों में धार्मिक उपयोग के लिए आरक्षित भूखंड और भवन मौजूद हैं। पुष्कर (अजमेर) - पवित्र सरोवर के पास मध्यप्रदेश सरकार की कई संपत्तियां स्थित हैं। हरिद्वार, रामेश्वरम, सोमनाथ, गया, अयोध्या में होल्कर, सिंधिया स्टेट के वक्त की धर्मशालाएं मौजूद हैं।

अब तक जो जानकारी आई उनमें सामने आई ये संपत्तियां

द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (वित्त विभाग)

- मुंबई (महाराष्ट्र)-एडवर्ड विला मुंबई कफ परेड में है। ससून डॉक कोलाबा इस ऐतिहासिक डॉक का कुछ हिस्सा और जमीन। वर्ली और आसपास - आवासीय और व्यावसायिक भूखंड हैं। मोदी कंपाउंड, गोरेगांव - 2.5 एकड़ जमीन है। किराएदार टेक वेंचर लिमिटेड कंपनी का कब्जा है। 77 करोड़ किराया भी बकाया है। कोर्ट में लंबित है। प्रिंसेस बिल्डिंग- 2295.16 वर्गमीटर की इस बिल्डिंग में 153 किरायेदार हैं। नई दिल्ली- लुटियंस में फ्लैट- भूखंड। वायनाड (केरल)- 554 एकड़ का बीनाची एस्टेट केरल सरकार ने 453 एकड़ जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए अधिग्रहित कर लिया है। एक हिस्से पर 160 परिवारों का कब्जा है। नागपुर (महाराष्ट्र)- शहर के बीच में लगभग 3 एकड़ जमीन पर बस डिपो और वर्कशॉप है। निगम कर्मचारियों के पुराने आवासों की भूमि भी मौजूद है। झांसी (उप्र)- शहर में 1373.80 वर्गमीटर जमीन बस डिपो की है। मालिकाना हक को लेकर मप्र और उप्र सरकार के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में विवाद लंबित है। आगरा, पुणे, हैदराबाद- यहां भी निगम के पुराने कार्यालय और कर्मचारी आवास थे। वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं हैं।

भोपाल सहित पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में अब तक 10 लाख 19 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए

भोपाल। केन्द्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम त्वरित गति से चल रहा है। जहां जहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पर समय पर बिलिंग तथा रीडिंग हो रही है तथा दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है। कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब तक 10 लाख 19 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए हैं। इनमें सर्वाधिक भोपाल शहर वृत्त में 04 लाख, 38 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए हैं। कंपनी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने का काम समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी की टीमें लगातार कार्य में जुटी हुई हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि नए टैरिफ आर्डर के अनुसार स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अब खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपयोग की गई बिजली पर 20 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है। कंपनी ने कहा है कि यह उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी।

लापता हुए भाई-बहन का सुराग 12 घंटे में, परिवार को सौंपा

पंढरीनाथ पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

इंदौर। पंढरीनाथ थाना क्षेत्र से लापता हुए दो मासूम बच्चों को पुलिस ने महज 12 घंटे में सुरक्षित खोज निकाला। मोती तबेला इलाके से गायब हुए बच्चों की तलाश में पुलिस ने नाले, सुनसान इलाकों, रैन बसेरों और शहर के कई संवेदनशील स्थानों पर सघन सर्च अभियान चलाया। आखिरकार दोनों बच्चे भिक्षावृत्ति उन्मूलन केंद्र में सुरक्षित मिले, जहां पुनर्वास दल उन्हें भटकता देख लेकर पहुंचा था।

घटना मंगलवार की है, जब काली टंकी क्षेत्र निवासी दो महिलाओं ने अपने 8 और 9 वर्षीय बच्चों के अचानक गायब होने की शिकायत पंढरीनाथ थाने में दर्ज कराई। सूचना मिलते ही डीसीपी जोन-4 सुनील मेहता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित की और तत्काल तलाश शुरू कराई। थाना प्रभारी सतीश पटेल के नेतृत्व में पुलिस ने आसपास के नालों और झाड़ियों में रातभर तलाशी अभियान चलाया।

बच्चों के संभावित मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उनकी तस्वीरें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, धर्मशाला और अन्य स्थानों पर भेजी गईं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से मदद मांगी गई। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल द्वारा कुछ बच्चों को संरक्षण में लेकर छावनी और स्नेहलतागंज स्थित केंद्रों में रखा गया है। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर बच्चों की पहचान की और दोनों मासूम सुरक्षित मिल गए।

पूछताछ में सामने आया कि बच्चे खेलते-खेलते मुख्य सड़क तक पहुंच गए थे, जहां पुनर्वास दल ने उन्हें अकेला देखकर संरक्षण में ले लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस अभियान में थाना प्रभारी के साथ उपनिरीक्षक यतींद्र मिश्रा, उपनिरीक्षक राजाराम पटेल, आरक्षक दीपक परिहार, जितेंद्र यादव और दिलीप की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी टीम की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना की।

समाधान योजना में 29 लाख 81 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने लिया लाभ

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि समाधान योजना में 15 मई तक 29 लाख 81 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। उन्होंने बताया है कि पिछले वर्ष 3 नवम्बर को समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत हुई थी। योजना 15 मई तक लागू थी।

मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में 29 लाख 81 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया है। कुल 1497 करोड़ 45 लाख रूपये जमा किये गये हैं, जबकि 473 करोड़ 39 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 91 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 834 करोड़ 55 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 331 करोड़ 60 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।

सीधी, मंदसौर, रायसेन, नर्मदापुरम्, नीमच, उज्जैन ग्रामीण, सागर शहर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं गुना जिलों की कार्यकारिणी जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियां की गई हैं।

प्रदेश कांग्रेस द्वारा सीधी, मंदसौर, रायसेन, नर्मदापुरम, नीमच, उज्जैन ग्रामीण, सागर शहर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं गुना जिलों की नवीन कार्यकारिणी जारी की गई है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक सुदृढ़ करना, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना है।

संगठन महासचिव डॉ. संजय कामले जी ने जानकारी देते हुए बताया कि नवगठित कार्यकारिणी में अनुभवी, समर्पित एवं सक्रिय कांग्रेसजनों को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी पदाधिकारी संगठन की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और कांग्रेस संगठन को और अधिक सशक्त बनाएंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में संगठनात्मक नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा शेष जिलों की कार्यकारिणी भी आगामी कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी।

मध्यप्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन

भोपाल। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है। इससे व्यापारी समुदाय के कल्याण के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहतर वातावरण निर्मित करने और प्रदेश के निर्यात को बढावा मिल सकेगा। समिति में मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकतम 10 सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वाणिज्यिक कर, वित्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण, खनिज साधन, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, पशुपालन एवं डेयरी, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, विमानन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन विभाग और सीईओ, राज्य नीति आयोग, क्षेत्रीय प्रमुख-भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय अधिकारी-नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वरिष्ठ प्रबंधक-भारतीय कन्टेनर निगम, सीजीएम-नाबार्ड, शाखा प्रबंधक-ईसीजीसी, एक्जीम बैंक, क्षेत्रीय प्रमुख-एपिडा, आयुक्त-एफएसएसएआई, सीईओ-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आधिकारिक-सदस्य होंगे। सीईओ-अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, संचालक-आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी को संस्था के पदेन सदस्य और राज्य प्रमुख-सीआईआई, फिक्की, फिओ, डिक्की, लघु उद्योग भारती एवं अन्य राज्य स्तरीय व्यापार समिति तथा संघ को शीर्ष चेम्बर्स से पदेन सदस्य मनोनीत किया गया है। प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल को सदस्य-सचिव नामित किया गया है। अध्यक्ष की अनमति से मध्यप्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा। जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी) के गठन एवं कार्य क्षेत्र का निर्धारण सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तावित कर समन्वय में अनुमोदन के बाद किया जायेगा। बोर्ड की बैठक कैलेंडर वर्ष में 4 बार अर्थात् 3 माह में एक बार आयोजित की जाएगी।

गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत व्यवधानों में आई उल्लेखनीय कमी

औद्योगिक उपभोक्ताओं ने की कंपनी के कार्यों की सराहना

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर के समस्त 11 केवी औद्योगिक फीडरों पर बेयर कंडक्टर को कवर्ड कंडक्टर में परिवर्तित किए जाने के फलस्वरूप गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत व्यवधानों में उल्लेखनीय कमी आई है। यह बात गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कंपनी के भोपाल सिटी सर्किल के महाप्रबंधक श्री प्रदीप सिंह चौहान द्वारा गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ आयोजित बैठक के दौरान कहीं। बैठक में पदाधिकारियों ने कंपनी द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि

उच्चदाब उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के साथ ही बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में कंपनी द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। एसोसिएशन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कलेक्टर भोपाल के साथ आयोजित बैठक में भी औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा कंपनी के कार्यों की सराहना की गई है तथा तकनीकी सुधारों एवं कवर्ड कंडक्टर कार्यों से विद्युत व्यवधानों में आई कमी को रेखांकित किया गया था। बैठक में महाप्रबंधक, सिटी सर्किल भोपाल श्री प्रदीप सिंह चौहान, उपमहाप्रबंधक (एसटीएम) श्री सुबोध सिंह एवं उपमहाप्रबंधक (एचटी मेंटेनेंस) श्री वैभव यादव उपस्थित रहे। वहीं गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष श्री विजय गौर, उपाध्यक्ष श्री मदनलाल, महासचिव श्री योगेश गोयल तथा संयुक्त सचिव श्री रक्षपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।